सितंबर 2025, वर्ष-1, अंक-3 पृष्ठ-40, मूल्य-50 / -रूपये

RNI NO. CTBIL/25/A1634

CHATURPOST
खबर वार्ता

GST

महंगाई के खिलाफ जीएसटी क्रांति

बड़ी प्रशासनिक सर्जरी...
पेज 19

हिन्दी समग्र ज्ञान की भाषा बने
पेज 25

2025

CHATURPOST

खबर वार्ता

20 तीन दिन की हिंसा और सत्ता परिवर्तन के पीछे का रहस्य

नेपाल में जेन जी ने तीन दिन में ही सत्ता को उखाड़ फेंका, नेपाल में अब सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की के नेतृत्व में अंतरिम सरकार काम कर रही है। अंतरिम सरकार में तीन मंत्रियों को शामिल किया गया है। इनमें कुलमान घिसिंग, रमेश्वर खनाल और ओम प्रकाश आर्याल शामिल हैं।

कवर स्टोरी

05 महंगाई के खिलाफ जीएसटी क्रांति...

अमेरिका की तरफ से शुरू किए गए टैरिफ वार के बीच भारत सरकार ने देश के नागरिकों को महंगाई से राहत देने के लिए जीएसटी में क्रांतिकारी बदलाव किया है। जीएसटी परिषद ने कई वस्तुओं और सेवाओं पर टैक्स जीरो...

कवर स्टोरी

08 क्रांतिकारी आर्थिक युग का सूत्रपात...

छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु देव साय ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में जीएसटी में जो सुधार किए गए हैं, वह देश के डेढ़ सौ करोड़ लोगों के जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आया है।

कवर स्टोरी

12 इस त्योहारी सीजन सारे रिकार्ड तोड़ने बाजार तैयार

जीएसटी की नई दरों के साथ ही यह त्योहारी सीजन भी दौड़ने को तैयार है। बाजार के जानकारों का अनुमान है कि माह भर के इस त्योहारी सीजन में प्रदेश में 1500 करोड़ से ज्यादा बरसेंगे।...

कवर स्टोरी

14 नया बस्तर निवेश, विकास और विश्वास की नई पहचान

बस्तर आज विकास की स्वर्णिम सुबह का प्रतीक बनकर उभर रहा है। जो क्षेत्र कभी उपेक्षा और अभाव की पहचान से जूझता था, वह अब निवेश, अवसर और रोजगार का नया केंद्र बन रहा है।

16 अलर्ट...
पीएम मोदी ने घोषणा की और ठगों ने बना लिया वेबसाइट

17 बिहार चुनाव...
हर बार बदल जाता है चुनावी समीकरण

18 सियासत
चमचों पर बड़ा बवाल, किधर जा रही कांग्रेस?

22 उज्जैन सिंहस्थ 2028
हर दिन एक लाख लोग कर सकेंगे बाबा महाकाल के दर्शन

24 खेल प्रोत्साहन
छत्तीसगढ़ से ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को सरकार देगी 21 लाख रुपए

30 कारोबार
भारत में लांचिंग के लिए तैयार नई स्कोडा ऑक्टाविया आरएस

34 अनंत चतुर्दशी पर विशेष
गणपतिजी विदा हो गए तो रिद्धि-सिद्ध शुभ-लाभ कैसे रहेंगे?

संपादक
शिवानी

प्रबंध संपादक
सुभाष श्रीवास्तव

मार्केटिंग व प्रसार
आशीष वर्मा

विधिक सलाहकार
मो. अजीज हुसैन
मो.93002-05215

ग्राफिक्स लेआउट डिजाइनर
कादिर खान

कार्यालय
रामा भवन बिलासपुर रोड
भनपुरी रायपुर -493221
वाट्सएप- 7587266011

प्रकाश एवं मुद्रक शिवानी द्वारा रामा भवन बिलासपुर रोड भनपुरी रायपुर से प्रकाशितव आसमा पब्लिशर्स इंडिया प्राालि. जयस्तंभ चौक रायपुर से मुद्रित
RNI-CTBIL/25/A1634
www.chaturpost.com

जनता के लिए अफसरों को ही बनना होगा सारथी

घूस का सिस्टम अभी तक इस कारण भी जीवित है, क्योंकि राजस्व प्रकरणों के शतप्रतिशत निपटारे का सिस्टम अब तक नहीं बन सका है। भले ही सीएम श्री साय ने राजस्व प्रकरणों को यथाशीघ्र निपटाने का फरमान दिया है, लेकिन अभी तक किसी जिले से खुशखबरी नहीं मिल सकी है। राजस्व मामले आमतौर पर पटवारियों की रिपोर्ट के आधार पर तय होते हैं और जब इसी स्तर पर प्रकरण को लंबित करने का बंदोबस्त कर दिया गया हो तो फिर तो कलेक्टर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। लाख कड़ाई के बाद भी राजस्व अमला अब भी घूसखोरी के प्रकरण में ज्यादा फंस रहा है। इसके अलावा तहसील ऑफिस का वास्ता सबसे ज्यादा किसानों को होता है।

छत्तीसगढ़ में सीएम विष्णु देव साय ने सुशासन का संकल्प लिया है। यह संकल्प केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लिया है। इसी के अनुरूप छत्तीसगढ़ में नीतियां बनाई जा रही हैं और इसका पालन किया जा रहा है। सुशासन की स्थापना के लिए सीएम श्री साय ने छत्तीसगढ़ के गांवों का धुआंधार दौरा किया था। इसके बाद कलेक्टर्स और एसपी की बैठक में भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि कहीं पर भी लापरवाही या उदासीनता के साथ भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनके आदेश के बाद कुछ जिलों में प्रशासन में परिवर्तन दिखा है। रायपुर, राजनांदगांव और बस्तर संभाग के कुछ जिलों के साथ जशपुर, अंबिकापुर, गौरेला पेंड्रा मरवाही जिलों में अफसर अब जनता के बीच जा रहे हैं। उनके बीच जमीन पर बैठ कर उनकी बातें सुन रहे हैं और सिस्टम की कमजोरियों को दुरुस्त करने के प्रयास में लगे हुए हैं। सीएम ने सभी कलेक्टरों को सप्ताह में एक दिन जनता से मिलने का वक्त भी तय करने का आदेश दिया है। जिलों से खबरें आ रही हैं कि जनता से अधिकारियों की मुलाकात हो रही है, मगर इसमें से कितनी जनता को राहत या सुविधा मिल रही है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। आमतौर पर जनता के आवेदनों को आगे बढ़ा कर सरकारी रिकॉर्ड में फाइल नस्तीबद्ध बता दिया जाता है। सरकारी ऑफिसों में शुरू किए गए ई-ऑफिस में यही फंडा लागू कर अफसर लंबित प्रकरणों के आंकड़ें कम से कम बता सकते हैं। इसलिए हर आवेदन का क्या निराकरण किया गया है, इसकी निगरानी की व्यवस्था भी मजबूत करने की आवश्यकता है। अन्यथा जनता भटकती रहेगी और सरकारी फाइल में सुकून नजर आता रहेगा। सरकार को यह भी सिस्टम लागू करना चाहिए कि जिलों के साथ तहसील और अनुभाग में भी अफसर जनता से एक दिन अवश्य मिलें। इससे निचले और जमीनी अफसरों को हकीकत की जानकारी मिलेगी और अधीनस्थ कर्मचारी जनता के साथ अन्याय नहीं कर सकेंगे। कोरबा के एक एसडीएम ने अपने ऑफिस के बाद घूस मांगने वालों की जानकारी सीधे फोन या व्यक्तिगत रूप से मिल कर देने का नोटिस जनता के नाम चिपका कर रखा है। इसके विपरीत व्यावहारिक बात यह है कि बहुत कम लोग घूस की शिकायत सार्वजनिक तौर पर कर पाते हैं। फिर भी पहल अच्छी है। घूस का सिस्टम अभी तक इस कारण भी जीवित है, क्योंकि राजस्व प्रकरणों के शतप्रतिशत निपटारे का सिस्टम अब तक नहीं बन सका है। भले ही सीएम श्री साय ने राजस्व प्रकरणों को यथाशीघ्र निपटाने का फरमान दिया है, लेकिन अभी तक किसी जिले से खुशखबरी नहीं मिल सकी है। राजस्व मामले आमतौर पर पटवारियों की रिपोर्ट के आधार पर तय होते हैं और जब इसी स्तर पर प्रकरण को लंबित करने का बंदोबस्त कर दिया गया हो तो फिर तो कलेक्टर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। लाख कड़ाई के बाद भी राजस्व अमला अब भी घूसखोरी के प्रकरण में ज्यादा फंस रहा है। इसके अलावा तहसील ऑफिस का वास्ता सबसे ज्यादा किसानों को होता है। किसी एक काम के लिए तहसील ऑफिस गए तो पूरा दिन निकल ही जाना है। ऊपर से यदि साहब दौरे या मीटिंग पर हैं, तो कार्यालय में मौजूद बाबू को आवेदन नहीं लेने या टरकाने का बहाना अवश्य मिल जाता है। सुशासन के लिए यह अच्छी बात है कि जिलों और तहसीलों की सेंया बढ़ गई है। कुछ नए जिलों में अब भी पूरा स्टॉफ या बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं, इस वजह से दिक्कत आ रही है। इसके बाद भी अब सरकार को चाहिए कि वह जिलों के मुखिया, चाहे वह कलेक्टर हो या एसपी, इन्हें जनता का सारथी बनाना होगा। अविभाजित मध्यप्रदेश में कलेक्टर और एसपी दिन हो या रात, खामोशी से छापे मार कर जनता का फीडबैक लेते थे या सिस्टम की जांच करते थे। कुछ कलेक्टर तो वेश बदल कर जनता के बीच जाते थे और उन्हें सही जानकारी मिलती थी। अब अधिकारी अपना दौरा कार्यक्रम पहले जारी कर देते हैं और उसके बाद उस इलाके की पीडीएस, खाद, स्कूल, आंगनबाड़ी का औचक निरीक्षण करते हैं। इससे कितना फायदा होता है, यह अफसर ही बता सकते हैं। जब तक सरकार इस स्तर पर निगरानी नहीं बढ़ाएगी, जनता का भला नहीं हो सकता।

महंगाई के खिलाफ जीएसटी क्रांति

एस. कुमार

अमेरिका की तरफ से शुरू किए गए टैरिफ वार के बीच भारत सरकार ने देश के नागरिकों को महंगाई से राहत देने के लिए जीएसटी में क्रांतिकारी बदलाव किया है। जीएसटी परिषद ने कई वस्तुओं और सेवाओं पर टैक्स जीरो कर दिया है। वहीं, अधिकांश वस्तुओं पर टैक्स में कमी की गई है। इससे आम और खास दोनों को लाभ होगा।

गुडस एंड सर्विस टैक्स हो गया गुड एंड सिंपल टैक्स

केंद्र सरकार ने जीएसटी में मौजूदा 4-स्तरीय टैक्स रेट ढांचे को बदलकर दो कर दिया है। इसमें एक 18% का स्टैंडर्ड रेट और दूसरा 5% का मेरिट रेट हैं। कुछ चुनिंदा वस्तुओं और सेवाओं के लिए 40% का विशेष डिमेरिट रेट लगाया गया है। आम आदमी की कई वस्तुएं जैसे हेयर ऑयल, टॉयलेट सोप बार, शैंपू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, साइकिल, टेबलवेयर, किचनवेयर, अन्य घरेलू सामान आदि पर जीएसटी 18% या 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

अब कई वस्तुओं पर जीरो टैक्स

बहुत अधिक तापमान वाला (यूएचटी) दूध, पहले से पैक और लेबल वाला छेना या पनीर पर जीएसटी 5% से घटाकर शून्य कर दिया गया है; सभी भारतीय ब्रेड (चपाती, पराठा, परोटा आदि) पर भी जीएसटी हटा दिया गया है। लगभग सभी खाद्य पदार्थों जैसे पैकेज्ड नमकीन, भुजिया, सॉस, पास्ता, इंस्टेंट नूडल्स, चॉकलेट, कॉफी, संरक्षित मांस, कॉर्नफ्लेक्स, मक्खन, घी आदि पर जीएसटी 12% या 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

किसानों को बड़ी राहत

कृषि वस्तुओं, मिट्टी तैयार करने या जुताई के लिए ट्रैक्टर, कृषि, बागवानी या वानिकी मशीनरी, कटाई या थ्रेसिंग मशीनरी, जिसमें पुआल या चारा बेलर, घास काटने की मशीन, कंपोस्ट मशीन आदि शामिल हैं, पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। हस्तशिल्प, संगमरमर और ट्रैवर्टीन ब्लॉक, ग्रेनाइट ब्लॉक, और मध्यम चमड़े के सामान जैसी श्रम-आधारित वस्तुओं पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। सीमेंट पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है।

जीवनरक्षक दवाओं पर जीरो टैक्स

33 जीवनरक्षक दवाओं और औषधियों पर जीएसटी 12% से घटाकर शून्य कर दिया गया है और कैंसर, दुर्लभ बीमारियों और अन्य गंभीर दीर्घकालिक रोगों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 3 जीवनरक्षक दवाओं और औषधियों पर जीएसटी 5% से घटाकर शून्य कर दिया गया है। अन्य सभी दवाओं और औषधियों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दंत चिकित्सा या पशु चिकित्सा या भौतिक या रासायनिक जांच के लिए इस्तेमाल होने वाले कई चिकित्सा उपकरणों और यंत्रों पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। कई चिकित्सा उपकरणों और आपूर्ति उपकरणों जैसे वैंडिंग गॉज, बैंडेज, डायग्नोस्टिक किट और रीजेंट, ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम (ग्लूकोमीटर), चिकित्सा उपकरणों आदि पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

पान मसाला और सिगरेट पर एमआरपी पर जीएसटी

पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, अनमैन्युफैक्चर्ड तंबाकू, जर्दा जैसे चबाने वाले तंबाकू पर लेन-देन मूल्य के बजाय खुदरा बिक्री मूल्य (आरएसपी) पर जीएसटी लगाया जाएगा।

आम जरूरत की चीजें सस्ती

एयर कंडीशनिंग मशीन, 32 इंच के टीवी (सभी टीवी पर अब 18% कर), डिशवॉशिंग मशीन, छोटी कार, 350 सीसी या उससे कम क्षमता वाली मोटरसाइकिल पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है।

इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में सुधार

हाथ से बनाए रेशे पर जीएसटी दर 18% से घटाकर 5% और मानव निर्मित धागे पर 12% से घटाकर 5% करके, मानव निर्मित कपड़ा क्षेत्र के लिए लंबे समय से लंबित इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में सुधार किया गया है। सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और अमोनिया पर जीएसटी दर 18% से घटाकर 5% करके उर्वरक क्षेत्र में इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में सुधार किया। नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों और उनके निर्माण के लिए पुर्जों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

सेवाओं से संबंधित अन्य बदलाव

रेस्टोरेंट सेवाओं की कर-देयता के संदर्भ में निर्देशित परिसर की परिभाषा में स्पष्टीकरण जोड़ने की सिफारिश की है, जिससे यह स्थिति स्पष्ट की जा सके कि एक स्टैंड-अलोन रेस्टोरेंट खुद को निर्देशित परिसर घोषित नहीं कर सकता है और फलस्वरूप, आईटीसी के साथ 18% की दर से जीएसटी का भुगतान करने का विकल्प नहीं प्राप्त कर सकता है।

घटेगा दाम, बढ़ेगा लाभ

- ट्रैक्टर की कीमत कम हो जाएगी
- ट्रैक्टर के कलपुर्जे सस्ते
- कृषि उपकरण सस्ते मिलेंगे
- उर्वरक होगा सस्ता
- कीटनाशक सस्ते होंगे
- फल-सब्जियां होंगी सस्ती
- मेवे हो जाएंगे सस्ते
- खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा
- स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा
- सौर ऊर्जा आधारित उपकरणों की भी कीमत कम होगी
- दूध और पनीर पर नहीं लगेगी जीएसटी
- तैयार या संरक्षित मछली पर जीएसटी कम
- शहद खरीदना भी सस्ता, कम हो जाएंगी कीमतें

जिम और सैलून पर टैक्स 5 प्रतिशत

7,500 रुपये प्रति यूनिट प्रतिदिन या उसके बराबर मूल्य वाली होटल आवास सेवाओं पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। आम आदमी के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सौंदर्य और शारीरिक स्वास्थ्य सेवाओं, जिनमें जिम, सैलून, नाई, योग केंद्र आदि शामिल हैं, पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

ऑटोमोबाइल सेक्टर पर बड़ा असर

350 सीसी या उससे कम सीसी वाली छोटी कारें और मोटरसाइकिल पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। बस, ट्रक, एंबुलेंस आदि पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। सभी ऑटो कलपुर्जों पर, चाहे उनका एचएस कोड कुछ भी हो, 18% की एक समान दर कर दी गई है; तीन-पहिया वाहनों पर इसे 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है।

कांग्रेस के समय 17 प्रकार के टैक्स और 13 तरह के सेस

प्रदेश के सीएम विष्णु देव साय ने कहा कि 101 वें संविधान संशोधन द्वारा 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू होने से पहले तक भारत में 17 प्रकार के टैक्स और 13 प्रकार के सेस लागू थे। प्रत्यक्ष कर की बातें करें तो आयकर की दर तो एक समय अधिकतम 97.5 प्रतिशत तक पहुँच गई थी। पिछले वर्ष 12 लाख सालाना की आय को टैक्स फ्री किया गया। अब जीएसटी में चार स्लैब के बदले दो ही स्लैब रखने, सभी उपयोगी वस्तुओं पर कर शून्य करने और अनेक उत्पादों में कर 10 प्रतिशत तक कम कर दिया गया है।

प्रत्येक परिवार को कम से कम 50 हजार की बचत

एक परिवार जो अपने जीवन यापन के लिए 3 से 3.5 लाख प्रत्येक वर्ष खर्च करता है, उन्हें काम से कम इतना लाभ मिलेगा। इसी तरह यह सुधार कृषि क्षेत्र के लिए वरदान जैसा है। ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, रोटावेटर में अलग-अलग तरह के जीएसटी घटाकर 5 प्रतिशत की गई है। यह किसान के लिए लागत सक्षम कृषि में सहायक होगी। जैव-कीटनाशक और सूक्ष्म पोषक तत्वों पर जीएसटी दर घटाई गई है। श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ एक कृषि प्रधान प्रदेश है। यहां की 80 फीसदी आबादी कृषि करती है। जीएसटी की छूट से 25 हजार से 63 हजार तक की बचत केवल एक ट्रैक्टर की खरीदी पर होगी।

छत्तीसगढ़ के किसानों को 200 करोड़ की बचत

प्रदेश के सीएम साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 30 से 35 हजार ट्रैक्टर प्रतिवर्ष बिकने का अनुमान है, जिससे यहां के किसानों को लगभग 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत केवल ट्रैक्टर में जीएसटी रेट कम होने से होगी। ट्रैक्टर के टायर में ही 7 हजार रुपये की बचत होगी। कृषि उपकरणों जैसे हार्वेस्टर, ट्रैक्टर टायर, बागवानी मशीन, खाद बनाने की मशीन, जैव कीटनाशक, मेंथॉल, सिंचाई मशीनों, कृषि मशीनरी, ड्रिप इरीगेशन सिस्टम, स्प्रिंकलर एवं अन्य पर अब केवल 5 प्रतिशत टैक्स होने से भी उत्पादन की लागत में कमी आएगी एवं मुनाफा बढ़ेगा।

स्वास्थ्य और जीवन बीमा पूरी तरह टैक्स फ्री

सीएम ने कहा कि इस कर छूट में एक सबसे उल्लेखनीय बिन्दु जो हमारे लिए निजी तौर पर भी संतोष देने वाला है, वह है स्वास्थ्य बीमा में जीएसटी को शून्य कर देना। स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा उत्पादों पर कर समाप्त करने का लाभ सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक है। यह कर छूट सभी के लिए बीमा का लक्ष्य पाने में मददगार होगा। सस्ते इलाज के संदर्भ में यह कदम ऐतिहासिक है।

तेन्दूपत्ता संग्राहकों को बड़ा लाभ होगा

सीएम साय ने कहा कि इसके अलावा तेंदू पत्ता और लघु वनोपजों की प्रोसेसिंग मशीन में जीएसटी दर कम करने से हमारे बस्तर-सरगुजा अञ्चल के संग्राहकों को बड़ा लाभ होगा। जनजातीय क्षेत्र में तेंदू पत्ता जैसे लघु वन्य उत्पादों की मांग अधिक बढ़ेगी, इससे प्रदेश को भी काफी लाभ होगा। छत्तीसगढ़ के लिए यह विशेष कर महत्वपूर्ण है। इसी तरह कोयले पर सेस हटाना भी महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ को आर्थिक सुधार और शानदार प्रबंधन के लिए केवल प्रोत्साहन राशि के मद में 6200 करोड़ रुपए मिले हैं।

90% सामान सस्ते हुए

सीएम साय ने कहा कि नए सुधार से सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्योगों को सबसे अधिक लाभ मिलेगा। रोजमर्रा की अनेक वस्तुएँ जैसे तेल, शैंपू, टूथपेस्ट, मक्खन, पनीर, सिलाई मशीन से लेकर ट्रैक्टर व उसके कलपुर्जे व अन्य कृषि उपकरण तथा व्यक्तिगत स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा, शैक्षणिक वस्तुओं के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक व ऑटोमोबाइल उत्पादों को किफायती बनाया गया है। जीएसटी कम होने का लाभ वस्त्र उद्योग को विशेष रूप से निर्यात के लिए होगा।

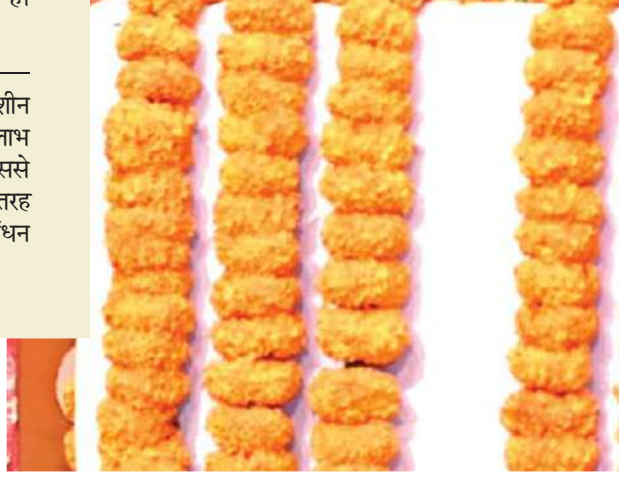

छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु देव साय ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में जीएसटी में जो सुधार किए गए हैं, वह देश के डेढ़ सौ करोड़ लोगों के जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आया है। आयकर में ऐतिहासिक छूट के बाद अब जीएसटी के स्लैब का सरलीकरण, इसके रेट में अभूतपूर्व सुधार आम आदमी के जीवन को खुशहाल करने वाले और व्यापार उद्योग को नई गति देने वाले हैं। साय ने कहा कि इससे न सिर्फ लोगों की बचत में ऐतिहासिक वृद्धि होगी, बल्कि जीएसटी कानूनों के सरलीकरण से अब व्यापारी भी अधिक सुगमता के साथ अपना कार्य कर सकेंगे।

क्रांतिकारी आर्थिक युग का सूत्रपात

जन-जन के जीवन को आसान बनाएगा जीएसटी सुधारः विष्णु देव साय

ग्राहक बनकर सीएम ने लिया जीएसटी रिफार्मस का जायजा

जीएसटी रिफार्मस का जायजा लेने सीएम विष्णुदेव साय खुद ग्राहक बनकर बाजार में पहुंच गए। वे रायपुर के एमजी रोड और आसपास के प्रमुख बाजारों का भी दौरा किया। इस दौरान उन्होंने व्यापारियों और उपभोक्ताओं से आत्मीय संवाद किया।

जीएसटी बचत उत्सव को लेकर जनभावनाओं से रूबरू होने सीएम राजधानी के एक मार्ट में पहुंचे। उन्होंने खुद ग्राहक बनकर 1,645 रुपए के घरेलू सामान की शॉपिंग की और यूपीआई से भुगतान भी किया। इस दौरान उन्होंने खरीदारी कर रहे लोगों से बातचीत की और जीएसटी दरों में कटौती से घरेलू सामानों के मूल्य में आए फर्क के बारे में जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने खरीददारों से चर्चा करते हुए जीएसटी सुधारों पर लोगों के विचार सुने। लोगों ने बताया कि दवाइयों और राशन की कीमत घटने से उन्हें बड़ी राहत मिली है। सीएम मुस्कुराते हुए बोले कि यही तो असली मकसद है कि सुधार की गूंज आम जनता तक पहुंचे।

जीएसटी कटौती नहीं यह बचत क्रांति

सीएम से चर्चा करते हुए खरीदारी कर रहे रिटायर्ड एयरफोर्स अधिकारी टीपी सिंह ने कहा कि आने वाले समय में जब इस दौर का इतिहास लिखा जाएगा, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुए जीएसटी सुधार को ऐतिहासिक बजट क्रांति के रूप में दर्ज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले हम जितने पैसों में 30 दिन का राशन लेते थे, अब उन्हीं पैसों से 40 दिन से अधिक का राशन ले पा रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री ही इतना बड़ा साहसिक निर्णय ले सकते थे, कोई और ऐसा नहीं कर पाता।

बाजारों में पहुंचे- राजधानी रायपुर स्थित जयस्तंभ चौक से महात्मा गांधी मार्ग होते हुए गुरुनानक चौक तक पैदल बाजार भ्रमण किया और जीएसटी बचत उत्सव का जायजा लेने विभिन्न प्रतिष्ठानों में पहुंचे। इस दौरान सीएम ने दुकानों में बचत उत्सव के स्टीकर भी लगाए और स्थानीय दुकानदारों और ग्राहकों से आत्मीय चर्चा की। बाजार भ्रमण के दौरान व्यापारियों में खासा उत्साह देखने को मिला। विभिन्न व्यापारी संगठनों और संचालकों ने सीएम का गर्मजोशी से स्वागत किया।

बचत में बढ़त

जीएसटी किया गया बदलाव आम आदमी के जीवन को खुशहाल करने वाले और व्यापार उद्योग को नई गति देने वाले हैं। इससे न केवल लोगों की बचत में ऐतिहासिक बढ़त होगी, बल्कि जीएसटी कानूनों के सरलीकरण से अब व्यापारी भी अधिक सुगमता के साथ अपना कार्य कर सकेंगे। यह कहना है छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी का। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू होने से पहले तक भारत में 17 प्रकार के टैक्स और 13 प्रकार के सेस लागू थे। इसके अलावा राज्य सरकारें भी मनमाने ढंग से कभी भी कोई भी कर आरोपित कर देती थी। पिछले वर्ष 12 लाख सालाना की आय पर टैक्स नहीं लागू करने का निर्णय लेने के बाद अब जीएसटी में चार स्लैब के बदले दो ही स्लैब रखने, सभी उपयोगी वस्तुओं पर कर शून्य करने और अनेक उत्पादों में कर 10 प्रतिशत तक कम कर देने से अब वास्तव में भारतीय अर्थव्यवस्था, जनता के लिए रामराज्य लाने वाला साबित होगा। ओपी चौधरी ने कहा कि नए सुधार से सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्योगों को सबसे अधिक लाभ मिलेगा. रोजमर्रा की अनेक वस्तुएं, ट्रैक्टर व उसके कलपुर्जे और अन्य कृषि उपकरण के साथ ही व्यक्तिगत स्वास्थ्य, जीवन बीमा, शैक्षणिक वस्तुओं के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक व ऑटोमोबाइल उत्पादों को किफायती बनाया गया है। उन्होंने कहा कि जीएसटी करदाता 2017 में 66.5 लाख से बढ़कर 2025 में 1.51 करोड़ हो गए हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में सकल जीएसटी संग्रह 22.08 लाख करोड़ रुपए रहा, जो केवल

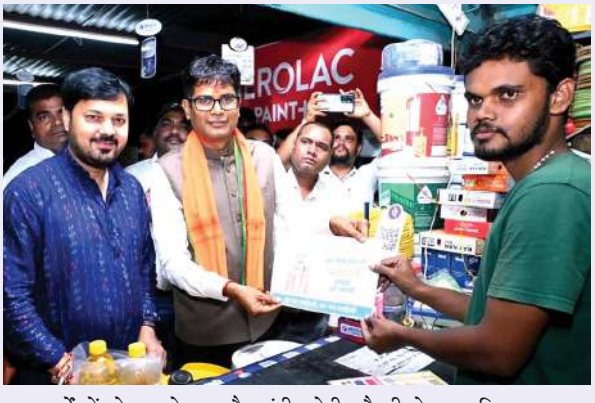

चार वर्षों में दोगुना हो गया है। मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि यह सुधार किसानों के जीवन में भी आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान करेगा। छत्तीसगढ़ की आबादी देश की जनसेंया का दो प्रतिशत से भी कम है लेकिन इस मद में हमें 41 प्रतिशत का 3.407 प्रतिशत हिस्सा मिलता है. इस वृद्धि के कारण पिछले 10-11 वर्ष में हमें एक लाख करोड़ रुपए से अधिक अतिरिक्त मिले हैं. मंत्री ओपी चौधरी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एजेंडे चुनावी और राजनीतिक एजेंडे से बड़े होते हैं. वह राष्ट्र हित में बड़े-बड़े फैसले लेने की ताकत रखते हैं. कोई भी फैसला होता है तो उसमें टैक्स का बेस बढ़ता है. टैक्स का पैसा या तो सरकार की जेब में जाता है या फिर जनता की जेब में जाता है. सरकार अब अपने जेब में न लेकर जीएसटी में बदलाव करके जनता की जेब में पैसा डाल रही है।

हर परिवार को न्यूनतम 40 से 50 हजार की बचत : अमित चिमानानी

जीएसटी में हुए कर-सुधार से आम आदमी के जीवन में अहम और सकारात्मक बदलाव आना तय है। केंद्र सरकार के इस ऐतिहासिक निर्णय से आम आदमी की बचत बढ़ेगी और लगभग 6 लाख करोड़ रुपए की खपत बढ़ेगी और आम आदमी के जीवन-स्तर व देश के आर्थिक परिदृश्य में क्रांतिकारी मजबूती आएगी। इन प्रावधानों से अब घर बनाना और घर चलाना बेहद सस्ता हो जाएगा। गुड एंड सर्विस टैक्स अब गुड और सिंपल टैक्स के नाम से भी जाना जाएगा।

घर बनाना हुआ सस्ता

सीमेंट, जो घर बनाने की एक बहुत जरूरी वस्तु है, के टैक्स रेट में 10 प्रतिशत की कटौती घर बनाने की लागत को कम करने जा रही है। अक्सर यह माना जाता है कि एक घर में 20 प्रतिशत लागत सीमेंट की ही होती है और अब उसके टैक्स रेट में 10 प्रतिशत की कटौती घर बनाने की लागत में सीधा-सीधा दो प्रतिशत कमी कर देंगे। घर में लगने वाले और उपयोग होने वाले कई सामान, जिनमें टीवी, रेफ्रिजरेटर, डेकोरेशन के सामान, पर भी टैक्स दरों में भारी कटौती से घर बनाने की लागत में महत्वपूर्ण कमी आएगी। यह कमी घर में उपयोग होने वाली वस्तुओं के हिसाब से 5 से 10 प्रतिशत की हो सकती है।घर चलाने के लिए जरूरी हर एक वस्तु पर अब टैक्स की दरों में कमी होने से घर चलाने का बजट भी प्रभावी रूप से कम होगा।

हर प्रदेश में ट्रिब्यूनल

हर प्रदेश में ट्रिब्यूनल खुलने से विवादों पर होने वाले खर्चों में भी भारी कटौती होगी। अन्य प्रदेशों में ट्रिब्यूनल होने से न सिर्फ खर्चा ज्यादा होता था बल्कि समय भी ज्यादा लगता था अब समय और पैसे दोनों की बचत होगी।

व्यापार होगा आसान

जीएसटी का रजिस्ट्रेशन अब केवल 3 दिन में मिलेगा जो काफी राहतमंद सिद्ध होगा। इससे व्यापार करने में आसानी के साथ अर्जेंट जीएसटी नंबर की आवश्यकता होने पर व्यापार का नुकसान नहीं होगा।

देश में खपत 6 लाख करोड़ तक बढ़ने की संभावना

भारत सरकार द्वारा किए गए इनकम टैक्स एवं जीएसटी के बदलाव के बाद भारत में खपत लगभग 6 लाख करोड रुपए से बढ़ेगी। इससे जीडीपी में बढ़ोतरी के साथ साथ रोजगार और आर्थिक विकास में भी ज्यादा तेजी दिखाई देगी।

केवल दो दरे होने से लिटिगेशन खत्म होगा

चार की जगह जीएसटी टैक्स की दो दरें होने से लिटिगेशन के मामलों में भारी कमी होगी। अक्सर यह देखा जाता था के कई वस्तुओं को लेकर उन पर लगने वाली कर की दर पर विवाद होता था और इसको लेकर कई प्रकार के लिटिगेशन कई स्तरों पर लंबित हैं। इससे व्यापारी वर्ग को भी परेशानी का सामना करना पड़ता था। अब चार की जगह दो कर दरे होने से ऐसे विवादों में भारी कमी आएगी।

7 दिन में रिफंड से एक्सपोर्ट सेक्टर में आयेगा बूम

जीएसटी का रिफंड अब केवल 7 दिनों में होगा जिससे एक्सपोर्ट में भारी उछाल आएगा। इससे स्वास्थ्य शिक्षा और खेती के खर्चों में भी भारी कमी आएगी। श्री चिमनानी ने कहा कि खेती के क्षेत्र में ट्रैक्टर, ट्रैक्टर टायर एवं पार्ट्स, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री मशीन्स पर जीएसटी की दरों में भारी कटौती की गई है। इलेक्ट्रॉनिक सामान 10 प्रतिशत सस्ते हो जाएंगे यानी 50 हजार रुपए मूल्य के सामान पर सीधे-सीधे 5 हजार रुपए की बचत होगी। इसी प्रकार 12 लाख रु. मूल्य की सीएनजी कार पर 1 लाख 20 हजार रुपए की बचत होगी और 20 हजार रुपए के बीमा पर लगभग 4 हजार रुपए की बचत होगी।

(लेखक भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता, अर्थशास्त्री, महालेखाकार के पूर्व सलाहकार व सीए)

इस त्योहारी सीजन सारे रिकार्ड तोड़ने बाजार तैयार

जीएसटी की नई दरों के साथ ही यह त्योहारी सीजन भी दौड़ने को तैयार है। बाजार के जानकारों का अनुमान है कि माह भर के इस त्योहारी सीजन में प्रदेश में 1500 करोड़ से ज्यादा बरसेंगे। साथ ही शासन के रा%सव में भी बढ़ोतरी होगी। जीएसटी की नई दरें लागू हो चुकी है बाजार भी पूरी तरह से उत्साहित है। कारोबारियों का कहना है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष त्योहारी सीजन में प्रदेश में कारोबार का नया रिकार्ड बनने वाला है। अकेले आटोमोबाइल सेग्मेंट को ही देखा जाए तो 22 सितंबर से लेकर 22 अक्टूबर के बीच ही प्रदेश में 70 हजार से ज्यादा दोपहिया और करीब आठ हजार कारों के बिक्री का अनुमान है। वहीं व्यावसायिक वाहनों की बिक्री अलग से होगी। कुछ कार कंपनियों ने तो 22 सितंबर से मिलने वाली छूट को अभी से लागू कर दिया है ताकि उपभोक्ताओं को अभी से इसका फायदा मिलना शुरू हो जाए।

नवरात्र का पहला दिन पंचमी और अष्टमी की जबरदस्त बुकिंग

नवरात्रि के पहले, पंचमी व अष्टमी के लिए दोपहिया व कारों की बुकिंग जबरदस्त रूप से की जा रही है। कारोबारियों के अनुसार प्रदेश भर में अभी तक की स्थिति में अकेले नवरात्रि के नौ दिनों में करीब 20 हजार दोपहिया और तीन हजार कारों की बिक्री का अनुमान है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र से जुड़े व्यापारियों का मानना है कि वाहनों पर जीएसटी की दर 28 से घटाकर 18 प्रतिशत करने के निर्णय से बुकिंग में तेजी आई है।

60 हजार से डेढ़ लाख तक सस्ती होंगी कारें

1200 सीसी से कम क्षमता की कारों व 350 सीसी तक की बाइकों पर 10 प्रतिशत जीएसटी की कटौती की जा रही है। शोरूम संचालकों के अनुसार 60,000 से डेढ़ लाख रुपये तक कारें सस्ती हो रही हैं। कंपनियां कुछ चुनिंदा ब्रांडों पर अतिरिक्त ऑफर भी दे रही हैं। ऐसे में आठ लाख रुपये तक की कारें 75000 रुपये तक सस्ती मिल सकेंगी। बाइकें भी सात हजार से लेकर 15,000 रुपये तक सस्ती हो जाएंगी।

इन पर लगेगा ज्यादा टैक्स

बाजार के जानकारों के मुताबिक 1200 सीसी से ऊपर की क्षमता वाली और एसयूवी कारों पर 28 की जगह 40 फीसदी जीएसटी लगाने की घोषणा हुई है। 350 सीसी से अधिक क्षमता के इंजन वाली बाइकों पर भी अब 28 की जगह 40 फीसदी टैक्स लगाया जाएगा।

25 से 30 फीसद ग्रोथ की संभावना

पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष आटोमोबाइल सेक्टर में त्योहारी सीजन में 25 से 30 फीसद ग्रोथ की संभावना है। 22 सितंबर से जीएसटी की नई दरें लागू हो रही है और अभी से बुकिंग जबरदस्त शुरू हो गई है।

कैलाश खेमानी, उपाध्यक्ष, राडा

जबरदस्त कारोबार की आस

घर का सपना संजोए लोगों के लिए अच्छा मौका है। जीएसटी की दरों में कमी के साथ ही रजिस्ट्री की दरें भी काफी कम हैं। रियल इस्टेट कारोबारी भी आफर देंगे। ऐसे में पिछले वर्ष की तुलना में रियल इस्टेट में 10-20% बढ़ोतरी की संभावना है।

आनंद सिंघानिया, मैनेजिंग डायरेक्टर, अविनाश ग्रुप

रियल इस्टेट भी भरेगा नई उड़ान

इस त्योहारी सीजन में रियल इस्टेट भी नई उड़ान भरने को तैयार है। जीएसटी दरों में कमी का फायदा रियल इस्टेट में भी मिलेगा। रियल इस्टेट कारोबारियों का कहना है कि अभी रजिस्ट्री की दरें भी कम है और बैंकों के ब्याज दरें भी सस्ती है। ऐसे में निश्चित रूप से रियल इस्टेट सेक्टर में पिछले वर्ष की तुलना में 20 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की आस है। रियल इस्टेट कंपनियां भी उपभोक्ताओं को ज्यादा से ज्यादा अच्छे आफर दे रहे है।

सराफा की गति बढ़ेगी

कीमतों में तेजी के चलते काफी समय से सुस्त पड़ा सराफा बाजार भी त्योहारी सीजन में अपनी रेतार बढ़ाएगा। ज्वेलर्स कंपनियों के साथ ही सराफा कारोबारी भी उपभोक्ताओं को लुभाने आकर्षक आफरों की बौछार करने की तैयारी में है। गहनों की नई रेंज के साथ ही आफरों का फायदा भी उपभोक्ताओं को मिलेगा।

खूब होगी कपड़ों की बिक्री

कपड़ा मार्केट में त्योहारी सीजन में कारोबार का नया रिकार्ड बनाने की तैयारी में है। संस्थानों में कपड़ों की नई रेंज आ गई है और संस्थानों द्वारा उपभोक्ताओं को लुभाने आकर्षक ऑफर भी ला रहे है। कूपन आफर के साथ ही सीधे छूट की भी तैयारी है। इसके साथ ही फूटवियर मार्केट भी दौड़ेगा।

नया बस्तर निवेश, विकास और विश्वास की नई पहचान

1. नक्सल उन्मूलन से विश्वास निर्माण तक - बदलता हुआ बस्तर
2. समावेशी विकास की ओर तेजी से अग्रसर बस्तर
3. औद्योगिक नीति 2024-30 से दी बस्तर को नई उड़ान
4. नियद नेल्ला नार योजना और पुनर्वास नीति से सशक्त हो रहा बस्तर

विशेष संवाददाता

बस्तर आज विकास की स्वर्णिम सुबह का प्रतीक बनकर उभर रहा है। जो क्षेत्र कभी उपेक्षा और अभाव की पहचान से जूझता था, वह अब निवेश, अवसर और रोजगार का नया केंद्र बन रहा है। यहाँ हर क्षेत्र–उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और पर्यटन–में समावेशी विकास की गूंज सुनाई दे रही है। यह बदलाव न केवल बस्तर की तस्वीर बदल रहा है, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के उज्ज्वल भविष्य की गाथा लिख रहा है।

निजी निवेश और समावेशी विकास

बड़े सार्वजनिक निवेशों के साथ-साथ लगभग 1,000 करोड़ का निजी निवेश भी सेवा क्षेत्र और एमएसएमई में किया जा रहा है। यह विविधीकृत विकास रोजगार के अवसरों को बढ़ाएगा और समावेशी व सतत विकास को सुनिश्चित करेगा। कुल मिलाकर लगभग 52,000 करोड़ की प्रतिबद्धताओं के साथ बस्तर औद्योगिक और सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन का नया केंद्र बन रहा है।

बड़े सार्वजनिक निवेश

बस्तर में एनएमडीसी द्वारा 43,000 करोड़ तथा सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल के लिए 200 करोड़ का निवेश किया जा रहा है। ये निवेश बस्तर की आधारभूत संरचना को मजबूती प्रदान कर रहे हैं।

बस्तर को मिला पहला 350 बेड का निजी अस्पताल

जगदलपुर में पहली बार 350 बेड का मल्टी-स्पेशियलिटी निजी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज स्थापित होने जा रहा है। इसके लिए रायपुर स्टोन क्लिनिक प्रा. लि. को इनविटेशन टू इन्वेस्ट पत्र जारी किया गया है। 550 करोड़ रुपये के निवेश और 200 रोजगार अवसरों के साथ यह परियोजना बस्तर की स्वास्थ्य सेवाओं को नई ऊँचाई देगी और इसे मेडिकल शिक्षा का केंद्र बनाएगी। इसके अतिरिक्त, जगदलपुर में 33 करोड़ रुपये के निवेश से एक और मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल तथा नवभारत इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज द्वारा 85 करोड़ रुपये के निवेश से 200 बेड का मल्टी-सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल स्थापित किया जाएगा। ये पहल न केवल आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करेंगी, बल्कि सैकड़ों युवाओं को रोजगार भी प्रदान करेंगी।

रेल-सड़क परियोजनाओं से आएगा बड़ा बदलाव

बस्तर के विकास को गति देने के लिए सरकार ने 5,200 करोड़ की रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें रावघाट-जगदलपुर नई रेल लाइन (3,513.11 करोड़) और केके रेल लाइन (कोत्तवलसा-किरंदुल) के दोहरीकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं। ये परियोजनाएँ न केवल बस्तर में यात्रा, पर्यटन और व्यापार को नई दिशा देंगी, बल्कि युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोज़गार और औद्योगिक अवसर भी सृजित करेंगी। बेहतर रेल कनेक्टिविटी से नक्सलवाद उन्मूलन के प्रयास और मजबूत होंगे तथा बस्तर विश्वसनीय निवेश और समावेशी विकास का केंद्र बनकर उभरेगा।

इसके साथ ही, बस्तर में 2300 करोड़ की सड़क विकास परियोजनाएँ भी स्वीकृत की गई हैं। कभी नक्सल प्रभावित क्षेत्र के रूप में जाना जाने वाला यह संभाग अब छत्तीसगढ़ के सबसे विकसित और समृद्ध क्षेत्रों में से एक बनने की राह पर है। राज्य और केंद्र सरकार मिलकर धमतरी-कांकेर-कोंडागांव-जगदलपुर मार्ग का एक वैकल्पिक रास्ता बना रही हैं, जो कांकेर, अंतागढ़, नारायणपुर के अबूझमाड़ होते हुए दंतेवाड़ा के बारसूर और आगे बीजापुर तक पहुँचेगा। इन परियोजनाओं से बस्तर के सभी जिलों तक पहुँचने के लिए कई रास्ते उपलब्ध होंगे, जिससे दूरियाँ कम होंगी और योजनाओं व विकास कार्यों की पहुँच और अधिक प्रभावी होगी। यह आधुनिक सड़क नेटवर्क न केवल आवागमन की सुविधा बढ़ा रहा है, बल्कि सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक प्रगति के नए द्वार भी खोल रहा है। इस प्रकार, बस्तर अब संघर्ष की भूमि से आगे बढ़कर संपर्क, समृद्धि और सुरक्षा का प्रतीक बन रहा है।

खाद्य प्रसंस्करण में नई शुरुआत – बीजापुर, नारायणपुर, बस्तर और कोंडागांव में आधुनिक राइस मिल और फूड प्रोसेसिंग इकाइयाँ स्थापित की जा रही हैं, जिससे किसानों को बेहतर मूल्य मिलेगा और स्थानीय युवाओं के लिए अनेक रोजगार अवसर सृजित होंगे।

एग्रीटेक और वैल्यू एडिशन- नारायणपुर जिले में पार्श्वा एग्रीटेक प्रतिवर्ष 2,400 टन परबॉयल्ड चावल का उत्पादन करेगी। 8 करोड़ रुपये के निवेश और नए रोजगार के साथ यह परियोजना बस्तर की कृषि उपज को वैल्यू एडिशन का नया आधार देगी।

वेलनेस और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में प्रगति- जगदलपुर में नमन् क्लब एंड वेलनेस सेंटर 7.65 करोड़ रुपये के निवेश और 30 रोजगार अवसरों के साथ स्थापित हो रहा है। वहीं पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में एएस बिल्डर्स एंड ट्रेडर्स तथा सेलिब्रेशन रिजॉर्ट्स एंड होटल्स बस्तर की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करेंगे।

डेयरी और कृषि-आधारित उद्योग – बस्तर डेयरी फार्म प्रा. लि. 5.62 करोड़ रुपये का निवेश कर दुग्ध उत्पादन और प्रसंस्करण को गति देगा। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और किसानों की आय में वृद्धि होगी।

निर्माण सामग्री और औद्योगिक विकास – पीएस ब्रिक्स और महावीर माइन्स एंड मिनरल्स जैसी कंपनियाँ ईंट और स्टोन क्रशर क्षेत्र में प्रवेश कर रही हैं, जिससे निर्माण गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और बुनियादी ढांचा सशक्त होगा।

वेयरहाउसिंग, लॉजिस्टिक्स और कोल्ड स्टोरेज – कांकेर, भानुप्रतापपुर और कोंडागांव में नए वेयरहाउसिंग केंद्र स्थापित हो रहे हैं। दंतेश्वरी कोल्ड स्टोरेज जैसी परियोजनाएँ किसानों की उपज को लंबे समय तक सुरक्षित रखने, बर्बादी घटाने और लाभ बढ़ाने में मदद करेंगी।

वुड, फर्नीचर और कृषि मशीनरी – माँ दंतेश्वरी वेनियर्स और अली फर्नीचर जैसी इकाइयाँ बस्तर की पारंपरिक कारीगरी को आधुनिक बाजारों से जोड़ेंगी।

आधुनिक उद्योगों की एंट्री - शंकरा लेटेक्स इंडस्ट्रीज 40 करोड़ रुपये के निवेश से सर्जिकल ग्लव्स निर्माण इकाई स्थापित करेगी, जिससे 150 रोजगार अवसर सृजित होंगे। यह भारत की स्वास्थ्य आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

पीएमएफएमई योजना के तहत सहयोग – पीएमएफएमई योजना अंतर्गत कांकेर, बस्तर और कोंडागांव जिलों के हितग्राहियों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई। कांकेर जिले के श्री मुकेश खटवानी (मेसर्स रूद्रा फूड्स एंड बेवरेजेस) को 35 लाख, बस्तर जिले की श्रीमती योगिता वानखेडे (मेसर्स माँ गृह उद्योग) को 5 लाख तथा कोंडागांव जिले की श्रीमती रागिनी जायसवाल (मेसर्स फिटनेस`यूल) को 5 लाख एवं 9.50 लाख की स्वीकृति मिली। कुल मिलाकर योजना के अंतर्गत ?49.50 लाख से अधिक की सहायता दी गई।

पीएमईजीपी योजना से सशक्तिकरण – पीएमईजीपी योजना अंतर्गत कांकेर जिले के हरीश कोमरा (रेडीमेड गारमेंट्स -9 लाख), सुरेश बघेल (हार्वेस्टर - 20 लाख), बस्तर जिले के चंद्रशेखर दास (मेसर्स दीक्षा टेंट हाउस - 8.80 लाख) और रेवेन्द्र राणा (मेसर्स राणा मोबाईल रिपेयरिंग - 7.50 लाख) को सहायता दी गई। वहीं कोंडागांव जिले के श्री सुरेश कुमार देवांगन (मेसर्स किसान मितान एग्रो) को ट्रैक्टर-ट्रॉली निर्माण के लिए 50 लाख का अनुदान स्वीकृत हुआ। इस प्रकार योजना के अंतर्गत 94.50 लाख की राशि वितरित की गई।

औद्योगिक नीति से नए अवसर – राज्य सरकार की औद्योगिक नीति के तहत स्थायी पूंजी निवेश हेतु भी अनुदान दिया गया। कांकेर जिले की साधना शर्मा (मेसर्स महावीर वेयरहाउस) को वेयरहाउस स्थापना के लिए 90 लाख की स्वीकृति मिली। इन पहलों से बस्तर संभाग में उद्यमिता और औद्योगिक विकास को गति मिल रही है और स्थानीय युवाओं व महिलाओं को रोजगार एवं आत्मनिर्भरता के अवसर मिल रहे हैं। कुल मिलाकर बस्तर में अब तक 967 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव आए हैं, जिससे 2100 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी, पर्यटन, निर्माण और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में यह निवेश लहर बस्तर को एक सच्चे निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित कर रही है।

बस्तर में औद्योगिक विस्तार के अवसर - बस्तर में औद्योगिक विकास की अपार संभावनाएं हैं। स्टील प्लांट के समीप समर्पित सीमेंट प्लांट, मोटर रिपेयर एवं वाइंडिंग, मशीन एवं फैब्रिकेशन शॉप्स, पंप रिपेयर जैसी सहायक इकाइयों को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही लोहा और इस्पात उद्योग से जुड़े पिग आयरन, टीएमटी बार, एंगल/चैनल, वायर रॉड्स और ब्राइट बार के उत्पादन की भी बड़ी संभावनाएँ हैं।

सीएम के 20 माह में 100+ दौर

सीएम विष्णु देव साय ने पिछले 20 महीनों में बस्तर के 100 से अधिक स्थानों का दौरा कर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास की नई आस और विश्वास का संचार किया है। नियद नेल्ला नार योजना के तहत सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और संचार सुविधाएँ दूरस्थ इलाकों तक पहुंची हैं। सुरक्षा शिविरों के 10 किमी दायरे में अब तक 81,090 आधार कार्ड, 49,239 आयुष्मान कार्ड, 5,885 किसान समान निधि लाभ, 2,355 उज्ज्वला कनेक्शन और 98,319 राशन कार्ड जारी किए गए। 21 सड़कों, 635 मोबाइल टॉवर, 18 उचित मूल्य दुकानों व 9 उप-स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण हुआ। अब तक 54 सुरक्षा शिविर स्थापित हुए हैं। पहली बार 28 गांवों (जैसे जगारगुंडा, पामेड) में बैंक खुले हैं और 50 से अधिक बंद स्कूल फिर से शुरू हुए हैं।

पीएम मोदी ने घोषणा की और ठगों ने बना लिया वेबसाइट

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 15 अगस्त के भाषण में प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोजगार योजना की घोषणा की थी। इसके तत्काल बाद साइबर ठगों ने इसी नाम से मिलती-जुलती वेबसाइट बना कर आम जनता को ठगना शुरू कर दिया है। इसमें रोजगार योजना के तहत पंजीकरण की सुविधा देने का दावा किया जा रहा है। जबकि भारत सरकार की वेबसाइट अलग ही है और अगस्त में प्रारंभ हो चुकी है। फर्जी वेबसाइट पर रोजगार पंजीयन के बहाने लोगों से वसूली की जा रही है। इसकी सूचना केंद्र सरकार को मिल गई है और लोगों को सतर्क करते हुए फर्जी साइट पर कार्रवाई के संकेत दिए गए हैं।

केंद्र सरकार ने सरकारी वेबसाइट की जानकारी लोगों को देते हुए फर्जी साइट से बचने की सलाह दी है। श्रम व रोजगार मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इन वेबसाइटों या उनकी गतिविधियों से केंद्र सरकार का किसी तरह का संबंध नहीं है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि इस वेबसाइट से बचें और अपनी व्यक्तिगत जानकारी उसमें साझा न करें और साथ ही किसी तरह का भुगतान भी न करें। मामला नौकरी का है, इस कारण लोग धोखे में आकर इस साइट का इस्तेमाल कर रहे हैं। फर्जी वेबसाइट भी बिल्कुल सरकारी वेबसाइट की तरह डिजाइन की गई है।

सरकारी सूत्रों ने बताया कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के संज्ञान में आया है कि https://viksitbharatrozgaryojana.org/ और https://pmviksitbharatrozgaryojana.com/ जैसी कुछ वेबसाइटें भारत सरकार के उपक्रम होने का झूठा दावा कर रही हैं और कथित तौर पर मंत्रालय के नाम से अखिल भारतीय स्थानों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित कर रही हैं।

सही वेबसाइट इस तरह है- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा अपने 12वें स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में घोषित प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोजगार योजना के तहत पंजीकरण की सुविधा प्रदान करने वाला प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोजगार योजना पोर्टल अगस्त में लाइव हो गया है। इस योजना के अंतर्गत प्रामाणिक जानकारी और सेवाओं के लिए, नियोक्ता प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोजगार योजना पोर्टल (https://pmvbry.epfindia.gov.in या https://pmvbry.labour.gov.in) पर जाकर एकमुश्त पंजीकरण प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने सभी नागरिकों, नियोक्ताओं और हितधारकों को धोखाधड़ी वाली वेबसाइटों और झूठे भर्ती दावों के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी है।

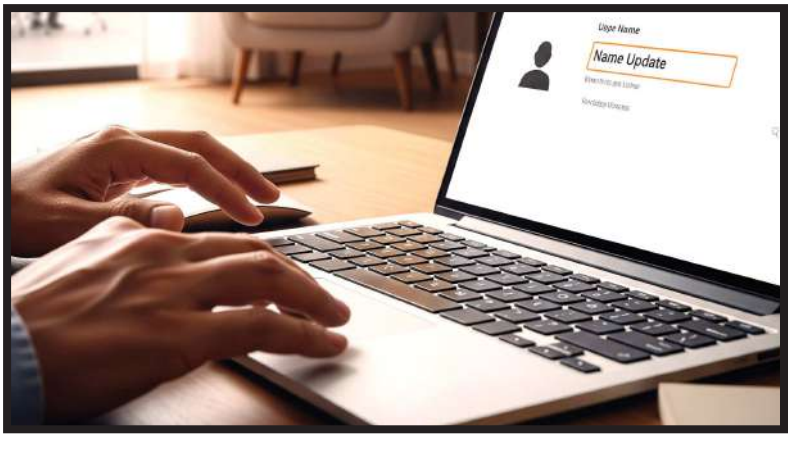

हर बार बदल जाता है चुनावी समीकरण

नवीन सिन्हा

राजधानी पटना से लेकर प्रदेश के गांवों तक चुनावी सरगर्मी के साथ सियासी समीकरणों की चर्चा तेज हो गई है। राहुल गांधी की वोट चोर गद्दी छोड़ यात्रा के बाद तेजस्वी यादव ने सितंबर में फिर एक यात्रा निकाली। सीटों के बंटवारे से पहले तेजस्वी यादव गठबंधन दलों के बीच अपनी पूरी ताकत दिखाना चाह रहे हैं। बिहार की राजनीति में जाति का बढ़ा महत्व है। यहां जातियों को लेकर नए- नए समीकरण बनाए और बिगाड़े जाते हैं। बिहार के सियासी उतार-चढ़ाव को समझने के लिए 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव सबसे बड़े उदाहरण हैं। दोनों ही चुनावों में मतदाताओं ने अलग-अलग संदेश दिया और गठबंधन की राजनीति ने नतीजों की दिशा ही बदल दी। दोनों ही चुनाव में वोट प्रतिशत और सीटों का गणित बदलने से सेाा की चाबी इधर से उधर होती रही। आंकड़े बताते हैं कि राजद-भाजपा जैसे विरोधी दल का जब वोट प्रतिशत बढ़ा तो इनकी सीटें घट गई और जब सीटें बढ़ी तो वोट प्रतिशत घट गए।

2015 में साथ थे लालू और नीतीश

वर्ष 2015 में हुए विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव साथ में थे। तब नीतीश की जदयू, लालू की राजद और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा। परिणाम आए तो राजद को सबसे ज्यादा 80 सीटें और 18.4 प्रतिशत वोट मिले। जदयू ने 71 सीटें जीतकर 16.8 प्रतिशत वोट हासिल किए। वहीं कांग्रेस को 27 सीटें मिलीं और उसका वोट प्रतिशत 6.7 प्रतिशत रहा।

इस चुनाव में भाजपा को वोट शेयर 24.4 प्रतिशत लेकिन पार्टी को केवल 53 सीट मिले। आंकड़ों से साफ है कि 2015 में महागठबंधन ने 178 सीटें जीतकर सत्ता पर कब्जा कर लिया, जबकि भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए को केवल 58 सीटें मिलीं। यह नीतीश-लालू के सोशल इंजीनियरिंग एकजुटता ने मोदी लहर में भी बड़ी जीत हासिल की।

पांच साल में बदल गया पूरा समीकरण

2020 का चुनाव आते-आते समीकरण पूरी तरह बदल गया। इस बार नीतीश बाबू भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए का हिस्सा बने। उधर, राजद ने कांग्रेस और वामदलों को साथ गठनबंधन जारी रखा। इस चुनाव में राजद का वोट प्रतिशत बढ़ा, पार्टी को 23.1 प्रतिशत वोट मिले, लेकिन सीटें 80 घटकर 75 हो गई।

इधर, भाजपा ने 19.5 प्रतिशत वोट के साथ 74 सीटें जीती। 2015 के मुकबाले 2020 में जदयू का प्रदर्शन कमजोर रहा। नीतीश की पार्टी को केवल 43 सीटें और 15.4 प्रतिशत वोट मिले। वहीं कांग्रेस का वोट प्रतिशत जरूर बढ़कर 9.5 प्रतिशत रहा। इतने वोट के बाद भी वह सिर्फ 19 सीटें जीत सकी। वाम दलों सीपीआई, सीपीआई-एमएल और सीपीएम को 16 सीटें और 4.25 प्रतिशत वोट मिले।

चमचों पर बड़ा बवाल किधर जा रही कांग्रेस?

विधानसभा चुनाव 2023 में हार के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस किस ओर जा रही है? वर्ष 2018 तक कांग्रेस की कमान पूर्व सीएम भूपेश बघेल के पास थी। निश्चित रूप से उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस को प्रदेशभर में सींचने का काम किया, धुआंधार दौरे कर माहौल बनाने में सफलता हासिल की। कांग्रेस पार्टी की जीत के बाद सीएम को लेकर काफी ऊहापोह की स्थिति बनी रही, मगर आखिरकार राहुल गांधी ने टीएस सिंहदेव और ताम्रध्वज साहू की जगह भूपेश को ही सरकार की कमान सौंप दी थी। पांच साल बाद हुए चुनाव में कांग्रेस की सरकार चली गई। अब नए अध्यक्ष के रूप में दीपक बैज कांग्रेस को संभालने की कोशिश करते दिख रहे हैं। कोशिश इसलिए, क्योंकि प्रदेश के दिग्गज नेताओं की लाइन अलग- अलग दिख रही है। नेताओं की लाइन अलग है, इस कारण उनके समर्थकों की लाइन भी दूसरी दिशा में जाते दिख रही है। हद तब हो जाती है जब प्रदेश मुयालय की बैठक में दो जिले के अध्यक्ष अपने नेताओं के पक्ष में आपस में ही भिड़ जाते हैं और नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत को कहना पड़ता है कि नेता अपने चमचों को संभालें। बात यहीं नहीं रुकती, रायपुर से बिलासपुर के दौरे पर गए डॉ.महंत को आगे कहना पड़ गया कि नेताओं को चमचों और बिच्छू से बच कर रहना चाहिए। अब चमचों की लड़ाई में कांग्रेस कहां जाती है, अगले विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए किस तरह खड़ी हो पाती है, इसके जवाब के लिए इंतजार करना होगा। प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर बार- बार अटकलें लगाई जा रही हैं। अभी श्री बैज अध्यक्ष हैं, मगर दो बड़े चुनावों में हार के बाद अध्यक्ष बदलने की मांग जोर पकड़ चुकी थी। अब पिछले दरवाजे से ही सही, फिर से बघेल को अध्यक्ष बनाने की मांग उठ रही है। जबकि नेता प्रतिपक्ष के रूप में डॉ. चरणदास महंत बिलासपुर और जांजगीर इलाके में सक्रिय दिख रहे हैं। उधर सरगुजा में पूर्व उपसीएम टीएस सिंहदेव चुनाव हारने के बाद भी सक्रिय दिखते रहते हैं। दूसरी ओर श्री बैज बस्तर पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। पूर्व सीएम भूपेश बघेल की बात करें तो वो अपने गृह क्षेत्र से रायपुर के बीच गतिविधियों में नजर आते हैं। एक खास बात यह है कि सरगुजा और बस्तर इलाके में पार्टी के ही कुछ दिग्गज नेता रुचि नहीं दिखाते। अब इसका क्या कारण है, यह राजनीतिक विश्लेषण का विषय है। दिग्गज नेताओं का इलाका इसी तरह सीमित रहा तो फिर अगले विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरने से पहले कांग्रेस को अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करना ही होगा।

प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट के सामने भी चलते रहे तीर

अगले विधानसभा चुनाव के लिए नेतृत्व की लड़ाई

चौबे जी ने जड़ा था छक्का

पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी रविंद्र चौबे ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल के जन्म दिन पर अपने दिल की बात कह दी थी। उन्होंने कहा कि चुनाव भूपेश जी के नेतृत्व में लड़ा जाना चाहिए। इनकी बात दूर तक गई और प्रदेश अध्यक्ष श्री बैज को कहना पड़ गया कि चौबे महाज्ञानी हैं। एक्शन और रिएक्शन के बीच श्री चौबे को प्रदेश मुयालय आना पड़ा और वहां पर श्री बैज से चर्चा हुई। चर्चा के बाद श्री चौबे ने कहा- प्रदेश अध्यक्ष परिपक्व हैं। उनके बयान से साफ है कि उन्होंने किसी तरह श्री बैज को मना लिया है और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होने वाली है। जबकि इससे पहले विरोधी गुट ने दावा किया था कि श्री चौबे पर कार्रवाई होगी और इसकी मांग की गई है। खबर है कि उनका बयान दिल्ली तक पहुंचा दिया गया था।

वोट चोरी छोड़ कर एक -दूसरे को बनाया निशाना

राहुल गांधी ने वोट चोरी के मसले को जन- जन तक पहुंचाने कहा है। इस सिलसिले में बिलासपुर में एक बड़ी सभा हुई। इस सभा में विशेष तौर पर प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट पहुंचे थे। वोट चोरी के मुद्दे पर सभी वक्ताओं ने अपनी बात तो रखी, मगर साथ ही साथ एक- दूसरे को निशाना बनाना भी नहीं छोड़ा। नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने बिलासपुर में एक बयान में कहा था कि चमचो, बिच्छू से दूर ही रहना चाहिए। इससे पहले उन्होंने रायपुर में कहा था कि नेताओं को अपने चमचों को संभालना चाहिए। यही मामला मंच पर भी दिख गया। वोट चोरी पर बोलते हुए पूर्व मंत्री शिव डहरिया संगठन के मसले पर आ गए। उन्होंने कहा कि हम किसी के चमचे नहीं हैं। इस तरह डहरिया ने सीधे महंत को जवाब दे दिया कि चमचा संस्कृति नहीं चल रही है। इसी मंच पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद थे। उन्होंने पायलट के सामने मामला संभालने और महंत को जवाब देने का प्रयास किया कि अब इस तरह की बातों को बंद करें और पार्टी हित में ही काम करने की बात सोचें।

अब कांग्रेस में दो कार्यकारी अध्यक्ष की तैयारी

गुटीय संतुलन बनाने की कोशिश में अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस में दो कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। चर्चा है कि एक कार्यकारी अध्यक्ष अनुसचित जाति वर्ग से और एक पिछड़ा वर्ग से बनाया जा सकता है। अभी अध्यक्ष बैज आदिवासी वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष बदलने की बात बार- बार जोर पकड़ती रही है, मगर नतीजा कुछ नहीं आ रहा है। पूर्व उपसीएम टीएस सिंहदेव अध्यक्ष का पद संभालने में रुचि दिखाते हुए कह चुके हैं कि पार्टी से मिलने वाली हर जिमेदारी को निभा सकते हैं। चर्चा को एक साल गुजर चुका है, पर अध्यक्ष का फैसला नहीं हो सका है। माना जा रहा है कि फिलहाल बैज ही अध्यक्ष बने रहेंगे।

बड़ी प्रशासनिक सर्जरी

मंत्रालय से बाहर हुए पिल्ले और साहू

डॉ. रोहित यादव को जनसंपर्क की कमान

मुख्य सचिव (सीएस) बदलते ही राज्य में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की गई है। इसमें 14 आईएएस प्रभावित हुए हैं। ऊर्जा विभाग संभाल रहे डॉ. रोहित यादव को जनसंपर्क विभाग का सचिव बनाया गया है। वहीं, राज्य कैडर के दो वरिष्ठ अफसरों रेणु पिल्ले और सुब्रत साहू को मंत्रालय से बाहर कर दिया गया है। जितेंदर यादव राजनांदगांव कलेक्टर बनाए गए हैं।

दो एसीएस हुए बाहर

रेणु जी पिल्ले (1991 बैच) को अध्यक्ष, व्यापमं के पद पर पदस्थ किया गया है। इसके साथ ही माध्यमिक शिक्षा मंडल का अतिरिक्त प्रभार उनको सौंपा गया है। वहीं, सुब्रत साहू (1992 बैच) को 1 अक्टूबर से सेवानिवृत्त हो रहे टोपेश्वर वर्मा की जगह अध्यक्ष, राजस्व मंडल, बिलासपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

बोरा को अतिरिक्त प्रभार

सोनमणि बोरा (1997 बैच) को प्रमुख सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। डॉ. रोहित यादव (2002 बैच) को सचिव, जनसंपर्क विभाग पदस्थ किया गया है। साथ ही ऊर्जा, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग और बिजली कंपनियों के अध्यक्ष का दायित्व जारी रहेगा। वहीं जनसंपर्क विभाग का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे पी. दयानंद (2006 बैच) को इस दायित्व से मुक्त किया गया है।

जिला स्तर पर भी बदलाव - राजनांदगांव कलेक्टर सर्वेश्वर भुरे के केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने की वजह से उनकी जगह जितेंदर यादव (2019 बैच) को कलेक्टर राजनांदगांव बनाया गया है। जबकि पठारे अभिजीत बबन (2022 बैच) को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत रायगढ़ पदस्थ किया गया है।

बंसल को विमानन विभाग की कमान

अविनाश चंपावत (2003 बैच) को धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग का अतिरिक्त प्रभार मिला है। वहीं मुकेश कुमार बंसल (2005 बैच) को सचिव, विमानन विभाग का दायित्व सौंपा गया है। इसी तरह अंकित आनंद (2006 बैच) को सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी विभाग और पर्यावरण संरक्षण मंडल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

भुवनेश यादव (2006 बैच) को योजना और 20 सूत्रीय कार्यक्रम का प्रभार, कुलदीप शर्मा (2014 बैच) को राज्य वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन का अतिरिक्त दायित्व दिया गया है। रवि मित्तल (2016 बैच) को संचालक विमानन और डॉ. फरिहा आलम (2016 बैच) को संचालक खाद्य के पद पर पदस्थ किया गया है।लोकेश कुमार को श्रम विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

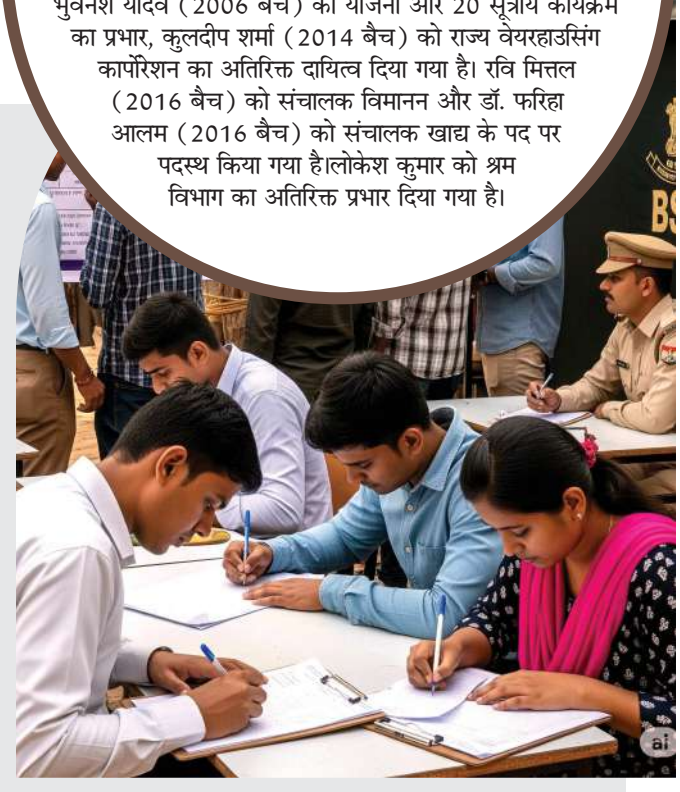

तीन दिन की हिंसा और सत्ता परिवर्तन के पीछे का रहस्य

विशेष संवाददाता

नेपाल में जेन जी ने तीन दिन में ही सत्ता को उखाड़ फेका, नेपाल में अब सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की के नेतृत्व में अंतरिम सरकार काम कर रही है। अंतरिम सरकार में तीन मंत्रियों को शामिल किया गया है। इनमें कुलमान घिसिंग, रमेश्वर खनाल और ओम प्रकाश आर्याल शामिल हैं।

राजशाही के खिलाफ सशस्त्र आंदोलन

नेपाल में पहले भी आंदोलन हो चुके हैं। 1996 में राजशाही के खिलाफ सशस्त्र आंदोलन हुआ था। फिर 10 वर्षों की हिंसा और अस्थिरिता के लंबे दौर से गुजरने के बाद 2006 में जन आंदोलन को अलविदा कहा। माओवादियों की सरकार बनी। लेकिन सरकारों से निराश जनता एक बार फिर सड़कों पर है। दस वर्ष तक चले इस गृहयुद्ध में 16,000 से अधिक लोग मारे गए, और 2006 में शांति समझौते के साथ इसका अंत हुआ।

नहीं रहा हिंदू राष्ट्र

नेपाल दुनिया एकमात्र हिंदू राष्ट्र था, लेकिन अब हिंदू राष्ट्र नहीं रहा बल्कि एक गणतांत्रिक देश है। नेपाल में 2008 में माओवादियों की जीत के बाद 240 साल पुरानी राजशाही खत्म हुई। नेपाल ने 2015 में नए संविधान के साथ खुद को एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया। इसके बावजूद नेपाल अपने अतीत की जंजीरों से पूरी तरह आजाद नहीं हो पाया है। लाल क्रांति का सपना अधूरा रह गया, लोकतंत्र लगातार उलझनों में घिरा है और राजशाही समय-समय पर सिर उठाकर अपने लिए अवसर की तलाश कर रही है।

राजशाही की वापसी की मांग

लोकतंत्र से निराशा के बीच नेपाल में राजशाही की वापसी की मांग ने फिर से जोर पकड़ा है. 2025 में काठमांडू और अन्य शहरों में हजारों लोग राजा वापस आओ, के नारे के साथ सड़कों पर उतरे पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह, जिन्हें 2008 में सत्ता से हटाया गया था, एक बार फिर सुर्खियों में हैं। उनके समर्थकों का मानना है कि राजशाही के दौर में कम से कम स्थिरता तो थी और भ्रष्टाचार आज की तुलना में कम था। ग्रामीण और पारंपरिक इलाकों में एक वर्ग आज भी मानता है कि राजशाही के दौर में सुरक्षा और स्थिरता थी । संवैधानिक राजशाही और हिंदू राष्ट्र की वकालत करने वाली राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी (आरपीपी) इस आंदोलन का नेतृत्व कर रही है। लोकतांत्रिक व्यवस्था से निराश नेपाल का एक वर्ग मुखर होकर राजशाही वापस लाने की मांग कर रहा है।

माओवादी विद्रोह

1996 में शुरू हुआ माओवादी विद्रोह नेपाल के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ था। 1996 से 2006 तक चले माओवादी आंदोलन का दावा था कि यह सामाजिक- आर्थिक ढांचे को बदलकर देश को न्यायपूर्ण और बराबरी वाला बनाने का संघर्ष है । माओवादियों के अनुसार ये आंदोलन राजशाही के खिलाफ था । इस आंदोलन में हजारों जानें गईं, गांव-गांव में विद्रोह का झंडा बुलंद हुआ और आखिरकार शांति समझौते के साथ माओवादी मुेयधारा की राजनीति में आए। माओवादियों ने लोकतंत्र और नए संविधान का वादा किया, जिसने ग्रामीण इलाकों व्यापक समर्थन हासिल किया।

चेहरा बदला, व्यवस्था नहीं

नेपाल की क्रांति के बाद माओवादी नेताओं जैसे पुष्पकमल दहल प्रचंड ने सत्ता हासिल तो की लेकिन नेपाल का संसदीय लोकतंत्र तमाशा बनकर रह गया। नेता सत्ता और भ्रष्टाचार के लिए तिकड़मबाजी में उलझ गए। जनता से किया गया समृद्धि, शिक्षा और स्वास्थ्य का सपना अधूरा ही रहा। आज लोग कहते हैं कि माओवादी क्रांति ने सत्ता का चेहरा बदला, व्यवस्था नहीं।

लगभग हर साल बदल जाते हैं प्रधानमंत्री

नेपाल में राजनीति कितनी अस्थिर रही इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2006 से 2025 तक नेपाल में 14 बार प्रधानमंत्री बदले हैं। इस दौरान पुष्प कमल दहल प्रचंड, माधव कुमार नेपाल, बाबूराम भट्टराई, सुशील कोइराला, केपी शर्मा ओली और शेर बहादुर देऊबा जैसे कद्दावर नाम हैं, जिन्होंने देश की सत्ता संभाली। 2008 में राजशाही के खात्मे के बाद नेपाल ने लोकतंत्र की राह पकड़ी, लेकिन यह राह स्थिरता से कोसों दूर रही। 17 सालों में 14 सरकारें बदल चुकी हैं, और कोई भी प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सका है।

सबसे गरीब देशों में शामिल है नेपाल

नेपाल दुनिया के सबसे गरीब देशों में आता है। विश्व बैंक और अन्य स्रोतों के अनुसार नेपाल दक्षिण एशिया में अफगानिस्तान के बाद दूसरा सबसे गरीब देश है। 2024 में नेपाल की प्रति व्यक्ति आय लगभग 1,381 डालर थी। 2025 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 2,878 डालर है जो नेपाल से दोगुनी से अधिक है।

उज्जैन आएंगे, तो ओंकारेश्वर में भी करेंगे दर्शन

उज्जैन आने वाले श्रद्धालुओं में 15 से 20 प्रतिशत के खंडवा जिले के ओंकारेश्वर दर्शन के लिए पहुंचने की संभावना है। इसे देखते हुए ओंकारेश्वर का भी ऑडिट कराया गया है। इसमें श्रद्धालुओं की संभावित संख्या, आने-जाने के रास्ते, प्रतिदिन दर्शन की क्षमता, नर्मदा में स्नान के लिए घाटों की उपलब्धता और क्षमता, पार्किंग व्यवस्था, खंडवा में श्रद्धालुओं को ठहराने की सुविधा और सभी जगह के लिए सुरक्षा प्रबंध की रूपरेखा बताई गई है।

सीएम ने की समीक्षा

सीएम डॉ. मोहन यादव ने उज्जैन में वर्ष 2028 में होने जा रहे सिंहस्थ की तैयारियों की समीक्षा की है। इस दौरान उन्होंने घाटों के विस्तार,सड़क निर्माण, शिप्रा को निर्मल बनाने के लिए किए जा रहे कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के लिए कहा है। उन्होंने निर्माण कार्यों के अतिरिक्त अन्य तैयारियां जैसे सुरक्षा, शाही स्नान के दिन की जाने वाली व्यवस्थाओं की अद्यतन जानकारी अधिकारियों से ली। बैठक में उज्जैन के जनप्रतिनिधि वर्चुअली शामिल हुए। उन्होंने भी आयोजन के संबंध में कई सुझाव दिए और सिंहस्थ से जुड़े पुराने अनुभव साझा किए।

हर दिन एक लाख लोग कर सकेंगे बाबा महाकाल के दर्शन

उज्जैन में 2028 में होने वाले सिंहस्थ महाकुंभ की तैयारी शुरू हो गई है। अनुमान है कि सिंहस्थ के दौरान उज्जैन में हर रोज एक लाख श्रद्धालुओं को भगवान महाकाल का दर्शन कराया जा सकेगा। इससे अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने पर प्रशासन उनके ठहरने की व्यवस्था करेगा और अगले दिन दर्शन कराया जाएगा। इस तैयारी के लिए पुलिस मुयालय ने उज्जैन के साथ ही खंडवा का भी सुरक्षा ऑडिट कराया है। इसमें दोनों जिलों की स्थानीय पुलिस ने यह पता लगाया कि भीड़ की दृष्टि से कौन-कौन से स्थान संवेदनशील हैं? सुरक्षा के कहां क्या प्रबंध किए जाने हैं? सीसीटीवी कैमरे कहां लगाए जाएंगे? इनका डिस्प्ले किस-किस जगह पर होगा? इसी रिपोर्ट के आधार पर अब विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए टेंडर प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी।

भारी फोर्स की होगी तैनाती

उज्जैन और खंडवा जिलों की आडिट रिपोर्ट मुख्यालय को मिल गई है। इसमें पिछले सिंहस्थ में किए गए प्रबंध और इस सिंहस्थ में श्रद्धालुओं की संभावित संख्या को देखते हुए प्रबंध के उपाय सुझाए गए हैं।

शाही स्नान के दिनों में सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में अलग से ऑडिट कर जरूरतों के बारे में बताया गया है। सभी जगह मिलाकर लगभग 60 हजार पुलिसकर्मियों को पदस्थ किया जाएगा। दूसरे राज्यों के पुलिस बल की भी मदद ली जा सकती है। सेटेलाइट रेलवे स्टेशन और बस स्टैंडों के आसपास पार्किंग की व्यवस्था और जरूरी सुरक्षा प्रबंध का भी आकलन किया गया है।

छत्तीसगढ़ के नए प्रशासनिक मुखिया विकास शील

वर्ष 2018 से वे केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भारत सरकार में रहे। उन्होंने केन्द्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग, जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में जल जीवन मिशन के मिशन डायरेक्टर के पद पर अपनी सेवायें दीं।

भारतीय प्रशासनिक सेवा 94 बैच के आईएएस अधिकारी विकास शील छत्तीसगढ़ के नए मुख्य सचिव (सीएस) बनाए गए हैं। विकासशील छत्तीसगढ़ के 13वें सीएस नियुक्त किए गए हैं। इसके पहले वे एशियन डेवलपमेंट बैंक, मनीला में कार्यकारी निदेशक के पद पर पदस्थ थे। विकास शील को आईएएस बनने के बाद मध्य प्रदेश कैडर मिला था। नवंबर 2000 में मध्यप्रदेश राज्य के विभाजन के बाद उन्हें छत्तीसगढ़ कैडर मिला। वे कोरिया, बिलासपुर और रायपुर जिले के कलेक्टर रहे हैं। वे स्कूल शिक्षा, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, सामान्य प्रशासन और स्वास्थ्य विभागों के सचिव पद पर तैनात रहे। इसके अलावा, वे अप्रैल 2007 से अप्रैल 2008 तक राजधानी रायपुर के कलेक्टर भी रहे हैं। वर्ष 2018 से वे केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भारत सरकार में रहे। उन्होंने केन्द्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग, जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में जल जीवन मिशन के मिशन डायरेक्टर के पद पर अपनी सेवायें दीं।

इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हैं नए सीएस

विकासशील का जन्म 10 जून 1969 को हुआ था। उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बी.ई. और फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से एम.ई. किया। उन्होंने सिरैक्यूज़ यूनिवर्सिटी, अमेरिका से लोक प्रशासन में मास्टर और एक्जीक्यूटिव मास्टर डिग्री और स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन एवं नीति में एडवांस्ड स्टडी का सर्टिफिकेट कोर्स किया है।

छत्तीसगढ़ से ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को सरकार देगी 21 लाख रुपए

छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष और सीएम विष्णुदेव साय ने बड़ी घोषणा की। ओलंपिक एसोसिएशन की वार्षिक आम सभा की बैठक में उन्होंने कहा कि अब छत्तीसगढ़ से ओलंपिक में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को 21 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। इन प्रतिभाओं को पहचान दिलाने और निखारने के लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयासरत है। हमने पूर्व में बंद हुए खेल अलंकरण समारोह को पुनः प्रारंभ किया है और जल्द ही उत्कृष्ट खिलाड़ी समान समारोह भी प्रारंभ किया जाएगा।

खेलो इंडिया के नए परिसरों की शुरुआत

सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया के नए परिसरों की शुरुआत की गई है। कुछ महीने पूर्व केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया का भी छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था, जहां हमने उनसे खेल अधोसंरचना के विस्तार को लेकर विस्तृत चर्चा की। विशेषकर ओलंपिक खेलों को लेकर खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने हेतु हमने विशेष तैयारी की है। ओलंपिक खेलों में प्रदेश के स्वर्ण पदक विजेताओं को तीन करोड़ रुपये, रजत पदक विजेताओं को दो करोड़ रुपये तथा कांस्य पदक विजेताओं को एक करोड़ रुपये देने का निर्णय लिया गया है। स्वाभाविक रूप से इससे खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन होगा। साय ने कहा कि हमारी सरकार का प्रयास है कि खेलों का बजट बढ़ाया जाए और कॉरपोरेट क्षेत्र की सहभागिता को भी प्रेरित किया जाए।

छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्तर के खेलों के आयोजन का होगा प्रयास

सीएम साय ने कहा कि वर्ष 2036 में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ओलंपिक खेलों के लिए भारत की मेजबानी का प्रस्ताव रखा है और अहमदाबाद शहर को इसके लिए प्रस्तावित किया गया है। स्वाभाविक रूप से केंद्र सरकार का पूरा ध्यान देश में खेलों की व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर है, ताकि एक दशक के भीतर हम खेलों के क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में उभर सकें। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ में भी हमें राष्ट्रीय स्तर के खेलों के आयोजन के लिए सामूहिक प्रयास करने होंगे।

हिन्दी समग्र ज्ञान की भाषा बने

राजाराम त्रिपाठी

(14 सितंबर हिन्दी दिवस पर विशेष)

हिंदी आज भी मंच की शेरनी है और देतर की बकरी ! जो नेता हिन्दी के नाम पर मंचों गरजते हैं, वही सचिवालय में अंग्रेजी की दुम हिलाते रहते हैं!

विश्व में हिंदी बोलने वालों की सेंया 60 करोड़ से अधिक है। तो इंटरनेट पर हिंदी सामग्री केवल 0.1 फीसदी है। उच्च शिक्षा के 85 प्रतिशत शोधपत्र अंग्रेज़ी में हैं। हिन्दी हिन्दुस्तान में ही उपेक्षित है।आजादी के साथ दशक बाद भी हिन्दी अपने देश की राष्ट्रभाषा नहीं बन सकी है। शिक्षा का माध्यम आज भी अंग्रेजी बनी हुई है। रूस, जर्मनी, फ्रांस जैसे देश अपनी मातृभाषा में शिक्षा देते हैं।

हिंदी दिवस के बहाने हम हर साल एक ही पुराने झुनझुने को बजाते कहते हैं, हिंदी हमारी आत्मा है, हिंदी हमारी पहचान है, हिंदी की जय हो। और अगले ही पल फाइलें, आवेदन पत्र, आदेश और अदालती कार्यवाही अंग्रेज़ी में ही चलते रहते हैं। यह वही स्थिति है। जिस पर कविवर भवानी प्रसाद मिश्र ने बरसों पहले कहा था,

हिंदी का दुखड़ा कोई सुनता नहीं, और गाता हर कोई है।

भारत की हिन्दी की ऐसी दुविधा संस्कृत में एक उक्ति बरबस जेहन में उभर आती है।

मातृभाषा न त्याज्या कदापि अर्थात मातृभाषा कभी भी त्यागने योग्य नहीं।लेकिन हम भारतीय अपनी भाषा के मामले में अपवाद साबित होने पर बड़े गर्व से कहते हैं।

आंकड़ें तो बोलते हैं, पर हम बहरे हैं। भारत में 46 करोड़ से अधिक लोग हिंदी मातृभाषा के रूप में बोलते हैं। विश्व स्तर पर हिंदी बोलने वालों की तादाद लगभग 60 करोड़ से अधिक मानी जाती है। गूगल की 2024 की एक रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेट पर हिंदी सामग्री की हिस्सेदारी केवल 0.1 फीसदी है, जबकि अंग्रेज़ी का हिस्सा 55 प्रतिशत से अधिक है। शिक्षा मंत्रालय के आँकड़े कहते हैं कि उच्च शिक्षा के 85 प्रतिशत से अधिक शोधपत्र आज भी अंग्रेज़ी में लिखे जाते हैं।

सवाल यह है कि इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद हिंदी ज्ञान-विज्ञान और तकनीक की भाषा क्यों नहीं बन पा रही?

हिंदी को 1950 से भारत की राजभाषा घोषित किया गया। पर सच्चाई यह है कि संसद, न्यायालय, विश्वविद्यालय और बड़े वैज्ञानिक संस्थान अभी भी अंग्रेज़ी की दासता से मुक्त नहीं हुए हैं। क्या यह विडंबना नहीं कि देश का प्रधानमंत्री हिंदी में बोलता है, पर उसी के मंत्रालयों के आदेश अंग्रेज़ी में लिखे जाते हैं?

यह वही दोमुंही स्थिति है जिसे अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार संसद में कहा था, राजभाषा हिंदी है, पर राज अंग्रेज़ी करता है।

मातृभाषा के मुद्दे पर हमें दुनिया से सीखने की ज़रूरत है । मुझे अपने हाल की रूस यात्रा में यह अनुभव हुआ। हर तरफ से साधन- संपन्न होने के बावजूद रूस ने तमाम वैश्विक दबाव और आंतरिक कठिनाइयों के बीच

अपनी भाषा पर अटूट विश्वास रखा है। विज्ञान हो या परमाणु तकनीक, साहित्य हो या अर्थशास्त्र, हर विषय की पढ़ाई-लिखाई वे अपनी ही भाषा में करते हैं। इसी तरह जर्मनी और फ्रांस तो भाषा-गौरव के लिए पहले से वियात हैं। अपनी यात्राओं के दौरान मैंने यह भी देखा कि थाईलैंड और कंबोडिया जैसे छोटे देश और इथियोपिया जैसा सबसे गरीब माने जाने वाला देश भी, अपना सारा शासकीय कामकाज और शिक्षा अपनी भाषा में ही करता है। और हम भारतीय अभी भी सोचते हैं कि हिंदी में विज्ञान पढ़ाने से छात्र कमजोर हो जाएंगे!

विश्व हिंदी, अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस, और हिंदी सप्ताह मनाने की परंपराएँ अब रस्म अदायगी से आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। आंकड़े बताते हैं कि बॉलीवुड फिल्में और हिंदी गीतों की वजह से विश्व के लगभग 80 देशों में हिंदी-समझने वालों की सेंया लगातार बढ़ रही है।अमेरिका, कनाडा, मॉरीशस, फिजी और खाड़ी देशों में हिंदी-भाषी समाज बड़ी ताकत बन चुका है। फिर भी विज्ञान, तकनीक और न्यायपालिका में हिंदी का स्थान हाशिए पर है।

आखिर दोष किसका है! दोष केवल अंग्रेज़ी या तथाकथित औपनिवेशिक मानसिकता का नहीं है। दोष उन नेताओं, नौकरशाहों और शिक्षा नीति निर्माताओं का है, जो जनता से हिंदी में वोट तो माँगते हैं, पर अपने बच्चों को अंग्रेज़ी माध्यम स्कूल भेजते हैं।

गांधीजी ने चेताया था, किसी राष्ट्र की आत्मा उसकी भाषा में बसती है।

पर हमने अपनी आत्मा को गिरवी रखकर शरीर को बेच दिया है।

यदि चीन, जापान, रूस, जर्मनी, फ्रांस जैसे देश अपनी भाषा में तकनीकी शिक्षा और शासन चला सकते हैं, तो भारत क्यों नहीं? हिंदी न केवल भारत में, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी एक मज़बूत दावेदार बन सकती है। बशर्ते हम इसे विज्ञान, तकनीक और प्रशासन की मुख्यधारा में लाएं।

हिंदी का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि यह केवल भावना की भाषा रहेगी या ज्ञान की भी भाषा बनेगी।

देश का राजनीतिक,आर्थिक और सामाजिक पुनर्जागरण

संजीव ठाकुर

1947 में भारत और पाकिस्तान ने एक साथ स्वतंत्रता की प्राप्ति की थी किंतु पाकिस्तान एक मुस्लिम राष्ट्र की अवधारणा धारण कर अलग दिशा में आगे बढ़ता गया जिसके फल स्वरुप आज पाकिस्तान विपन्न और गरीब देश बन गया है। दूसरी तरफ भारत एक लोकतांत्रिक, जनतांत्रिक अवधारणा की दिशा में नई-नई विकास के सोपनो को प्रतिपादित कर आगे बढ़ता गया। भारत वैश्विक स्तर पर सामरिक आर्थिक एवं अन्य विषयों पर काफी हद तक प्रगति प्राप्त कर चुका है।भारत ने आश्चर्यजनक रूप से देश को विकसित मजबूत एवं सशक्त बना दिया है ।

भारतीय परिदृश्य और संदर्भ में भारत में विगत एक दशक में व्यापक तथा आमूल चूल परिवर्तन देखे गये हैं। राजनीतिक परिदृश्य में उत्तरदायित्व आधारित शासन प्रशासन-प्रणाली, सांस्कृतिक विमर्श में सनातनी सांस्कृतिक सेयता-गौरव की पुनर्प्राप्ति और आर्थिक नीतियों के संरचनात्मक सुधारों ने देश की दिशा और दशा तय की है। इन नई विचारधारा एवं रणनीति ने भारत को न केवल आंतरिक रूप से सशक्त किया बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी एक निर्णायक शक्ति के रूप में स्थापित किया।

भारतीय राजनीति में पिछले दो दशकों का सबसे बड़ा परिवर्तन रिपोर्ट कार्ड राजनीति का उदय रहा, जिसमें आम जनता और राजनीतिक नेताओं और दलों का मूल्यांकन उनके किए गए कार्यों और परिणामों के आधार पर कसौटी पर कसा जाने लगा है।

संवैधानिक और नीतिगत स्तर पर कई ऐतिहासिक कदम उठाए गए। 2019 में अनुच्छेद 370 का निरसन और जेमू-कश्मीर का पुनर्गठन केंद्र की सेत और मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति तथा विचारधारा का प्रतीक बना। तीन तलाक कानून ने मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम रखा। वहीं नागरिकता संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रीयता और शरणार्थी नीति पर नई विचारों की श्रृंखला को जन्म दिया। भारत की परंपरागत लोकतांत्रिक विरासत को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के लिए नया संसद भवन, ई-संसद और डिजिटलीकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य को शामिल किया गया है। दूसरी तरफ विपक्ष की भूमिका, मीडिया की स्वतंत्रता और चुनावी राजनीति में सोशल मीडिया तथा धनबल के प्रभाव ने लोकतांत्रिक विमर्श को चुनौतीपूर्ण और प्रभावशाली भी बनाया गया है।

नये भारत की संकल्पना और अवधारणा को केवल राजनीति या अर्थव्यवस्था तक सीमित परिसीमित नहीं रखा गया है बल्कि सांस्कृतिक क्षेत्र के व्यापक फलक पर भी इसका गहरा असर और परिणाम परिलक्षित हुए हैं । भारत की महान अर्वाचीन योग और आयुर्वेद जैसी परंपरा को वैश्विक स्तर प्रचारित प्रसारित कर नई अवधारणा तथा पहचान प्रदान की गई है। अयोध्या में राममंदिर निर्माण ने भारतीय परंपरा और धार्मिक-सांस्कृतिक आकांक्षाओं की विशाल अवधारणा को मूर्त रूप दिया गया है। शिक्षा और पाठ्यपुस्तकों में भारतीय ओयानों और इतिहास को नवीन स्वरूप देने के प्रयास किए गए हैं। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं को पुष्पित पल्लवित करने के प्रयासों को संपूर्ण प्रोत्साहन दिया गया। साथ ही, सांस्कृतिक कूटनीति नवीन अवधारणा के माध्यम से भारत ने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपनी पहचान और अधिक सुदृढ़ रूप से विस्तारित की है। हालाँकि, इस सांस्कृतिक पुनर्जागरण के साथ अनेक कठिन एवं दुष्कर चुनौतियाँ भी रहीं हैं। बहुलतावाद और अल्पसेंयक अधिकारों पर उठते सवाल तथा परंपरा बनाम आधुनिकता की खींचतान समाज में गूढ विचार विमर्श का विषय बनी रही।

आर्थिक पुनर्जागरण के संदर्भ में यही कहा जा सकता है कि भारत की अर्थव्यवस्था ने इस दशक में उल्लेखनीय और अभूतपूर्व प्रगति प्राप्त की है । मेक इन इंडिया ने विनिर्माण और रक्षा उत्पादन को बढ़ावा दिया। जीएसटी (2017) ने कर संरचना को एकीकृत और पारदर्शी बनाया। जीएसटी को 2025 में 22 सितंबर से नवीन संशोधन कर एकदम सरल एवं स्पष्ट कर काफी हद तक सस्ता करके आम जन को बड़ी राहत पहुंचाई है। डिजिटल इंडिया, जनधन योजना ने वित्तीय समावेशन और नकदी रहित लेन-देन की दिशा में क्रांतिकारी बदलाव लाए।

स्टार्टअप इंडिया ने उद्यमिता और नवाचार को प्रोत्साहित किया। इसके परिणामस्वरूप भारत आज विश्व की पाँचवीं सबसे बड़ी सशक्त अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। विदेशी निवेश वृद्धि, रेलवे और सड़क निर्माण में गति तथा बिजली और डिजिटल नेटवर्क का विस्तार इस आर्थिक पुनर्जागरण के प्रमुख संकेतक रहे।इसके बावजूद बेरोजगारी की समस्या, ग्रामीणङ्कशहरी असमानता और आय-विभाजन जैसी बड़ी और गंभीर चुनौतियाँ भारत देश के आर्थिक परिदृश्य को संतुलित होने से रोकती रही हैं। कृषि सुधार अभी तक आधे अधूरे रह गए और हरियाणा पंजाब तथा अन्य प्रदेशों में किसान आंदोलनों ने यह यह साफ तथा स्पष्ट संकेत दिया कि विकास की अवधारणा सबके लिए समान रूप से सुलभ नहीं है।

अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य- भारत ने पिछले दशक में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी नई पहचान बनाई ग्लोबल साउथ के नेता के रूप में भारत की भूमिका स्पष्ट हुई। 2023 में आयोजित द्20 सेमेलनों में भारत ने वैश्विक मुद्दों पर संतुलित और निर्णायक नेतृत्व प्रस्तुत किया। चीन में हुए शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में 10 महत्वपूर्ण देशों के साथ 27 देशों ने भारत चीन और रूस पर अपना विश्वास जाहिर कर यूरोपीय शक्तियों एवं मनमानी का खुला विरोध किया है, जिसमें भारत पर अमेरिका द्वारा 50% लगाए गए टैरिफ का भी खुला विरोध हुआ है। रूस, चीन और पड़ोसी देशों के साथ संतुलित कूटनीतिक संबंधों ने भारत की स्थिति को और सशक्त मजबूत किया।पिछले दस वर्षों का भारत राजनीतिक दृढ़ता, सांस्कृतिक आत्मगौरव और आर्थिक नवाचारों से परिपूर्ण रहा है। यह अवधि भारतीय लोकतंत्र को नई परिभाषा देने, सांस्कृतिक मूल्यों को पुनर्जीवित करने और आर्थिक संरचना को मज़बूत करने में महत्वपूर्ण रही। हालाँकि असमानता, बेरोजगारी और राजनीतिक ध्रुवीकरण जैसी विकराल चुनौतियाँ अब भी बनी हुई हैं, फिर भी यह कहना उचित होगा कि यह दशक भारत के लिए राजनीतिक-सांस्कृतिक-आर्थिक पुनर्जागरण का समय रहा है, जिसने भारत को वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था में निर्णायक शक्ति बना दिया है। भारत की सनातनी सांस्कृतिक विरासत, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और भारत की सामरिक शक्ति में इजाफा होकर पिछले एक दशक में भारतीय जनमानस की एकजुटता एवं देश के नेतृत्व की कार्य कुशलता के परिणाम स्वरूप भारत का सेमान और कद वैश्विक परिदृश्य में काफी हद तक ऊंचा हुआ है।

लेखक
चिंतक स्तंभकार, रायपुर छत्तीसगढ़

समस्याओं में छिपा है समाधान खोज कर तो देखिए

एक युवक प्राइवेट कंपनी में कार्यरत था। वह अपनी जिंदगी से खुश नहीं था। वो हर समस्या से परेशान था और उसी के बारे में सोचता रहता था। एक बार शहर से कुछ दूरी पर महात्मा का काफिला रुका। जब उस युवक को पता चला तो वह भी दर्शन के लिए उनके पास पहुंचा।

महात्मा जी के पास सैकड़ों भक्त अपनी परेशानी लेकर आए हुए थे। जब उस युवक का नम्बर आया तो उसने कहा, मैं अपनी जिंदगी से बहुत दु:खी हूं। आप कोई ऐसा उपाए बताएं कि मेरी सभी परेशानियां दूर हो जाएं। महात्मा जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा, आज बहुत देर हो गई है मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर कल दूंगा। लेकिन तुम मेरा एक छोटा सा काम करोगे। हमारे काफिले में लगभग सौ ऊंट है, ऊंट की देखभाल करने वाला बीमार है। मैं चाहता हूं तुम इन ऊंटों की देखभाल करो। जब सभी ऊंट बैठ जाएं तो तुम सो जाना। इतना कहकर महात्मा जी अपने तंबू में चले गए। दिन हुआ तो महात्मा जी ने उस युवक से पूछा, बेटा क्या तुम्हें अच्छी नींद आई। युवक ने कहा, मैं एक पल के लिए भी नहीं सो पाया। मैनें सभी ऊंटों को बैठाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कोई न कोई ऊंट फिर खड़ा हो जाता। महात्मा जी बोले, मैं जानता था यही होगा। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि ये सारे ऊंट एक साथ बैठ जाएं। युवक नाराज हो गया।

वह बोला, जब आपको पता था तो आपने ऐसा करने के लिए क्यों कहा? तब महात्मा जी ने कहा, देखो जब तक एक समस्या का समाधान करने की कोशिश करोगे तो दूसरी समस्या खड़ी हो जाएगी। जब तक यह जीवन है ये समस्याएं बनी रहेंगी। कभी कम तो कभी ज्यादा। इसलिए इन समस्याओं का सामना करते हुए जीवन का आनंद लो।

कुदरती माहौल में सैर अवसाद दूर करने में मददगार

अवसाद का खतरा कम करने में कुदरती माहौल की सैर मददगार हो सकती है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के अनुसंधानकर्ताओं ने पाया है कि जो लोग करीब 90 मिनट तक कुदरती माहौल में चलते हैं उनके मस्तिष्क के उस क्षेत्र में गतिविधियां कम हो जाती हैं जिस क्षेत्र का संबंध अवसाद के एक प्रमुखकारक से होता है। लेकिन भीड़भाड़ वाले शहरी इलाकों की सैर से यह लाभ नहीं मिल पाता। इस अध्ययन के सह लेखक ग्रेचेन डेली ने बताया 'ये नतीजे बताते हैं कि तेजी से शहरीकरण की ओर बढ़ रही दुनिया में प्राकृतिक इलाके मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ' ग्रेचेन डेली स्टैनफोर्ड वुड्स इन्स्टीट्यूट फॉर द एनवायरनमेंट के एक वरिष्ठ फेलो हैं।

दुनिया की आधी आबादी शहरों में रह रही है और आने वाले दशकों में यह आंकड़ा बढ़ कर 70 फीसदी होने का अनुमान है। प्रकृति से अलगाव और शहरीकरण जिस तरह बढ़ रहा है उससे अवसाद जैसी मानसिक समस्याएं भी बढ़ रही हैं। अध्ययन के सह लेखक जेम्स ग्रॉस ने बताया 'ये नतीजे महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये तर्कयुक्त हैं।'

बादाम खाकर कैंसर से बचा जा सकता है

बादाम, जिसे अंग्रेजी में नट भी कहते हैं, खाने से कुछ खास प्रकार के कैंसर से बचा जा सकता है। यह हालांकि टाइप-2 मधुमेह में कारगर नहीं होता है। यह बात एक अध्ययन में कही गई। इस अध्ययन में अध्यनकर्ताओं ने 30,708 मरीजों पर अध्ययन किया। अध्ययन की रपट शोध पत्रिका न्यूट्रीशन रिव्यूज में प्रकाशित हुई है। मुख्य अध्ययन के लेखक और मिनेसोटा के रोचेस्टर में मायो क्लिनिक के शोधार्थी लैंग वू ने कहा, हमारे अध्ययन में पता चलता है कि बादाम खाने से कैंसर का जोखिम कम होता है। इस जानकारी का उपयोग जीवन में किया जा सकता है।

वू ने कहा, हार्ट डिजीज पर बादाम के लाभदायक प्रभाव की पहले से मौजूद जानकारी को इस अध्ययन निष्कर्ष के साथ मिलाया जाए, तो इसका अर्थ यह निकलता है कि जो व्यक्ति कैंसर और ह्रदय रोग को जोखिम कम करने के लिए बेहतर आहार अपनाना चाहते हैं, वे अपने खान-पान में बादाम को शामिल कर सकते हैं। उन्हें कैलोरी और वसा की मात्रा को देखते हुए विभिन्न बादामों में से सही बादाम चुनना होगा। शोधार्थियों ने बताया कि पहले के शोध में भी बादाम के रोग निवारक गुणों का पता चला है, लेकिन अलग-अलग प्रकार के कैंसर में इसके असर के बारे में सटीक जानकारी का अभाव है। मायो क्लिनिक और मिनेसोटा के मिनियापोलिस में स्थिति मिनेसोटा विश्वविद्यालय के शोध लेखकों ने कहा विभिन्न प्रकार के कैंसर के साथ बादाम के प्रभाव को

लेकर और अध्ययन किए जाने की जरूरत है। शोध लेखकों ने कहा, बादाम खाने से कोलोरेक्टल कैंसर, इंडोमेट्रियल कैंसर और पैंक्रिएटिक कैंसर का जोखिम घटता है, लेकिन अन्य प्रकार के कैंसर और टाइप-2 मधुमेह के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता है। समग्र तौर पर कहा जा सकता है कि बादाम खाने से कैंसर से रक्षा होती है।

सुनील दत्त उनकी यादें और फिल्म

सुनील दत्त का 6 जून 1929 झेलम पाकिस्तान में जन्म हुआ था। मृत्यु 25 मई 2005। सुनील दत्त का असली नाम बलराज दत्त था। सुनील दत्त शुरू से ही प्रतिभा के धनी थे वो भारतीय फिल्मों के बतौर विख्यात अभिनेता, निर्माता व निर्देशक जाने जाते थे। उन्होंने कुछ पंजाबी फिल्मों में भी अभिनय किया।

सुनील दत्त ने अपने छह दशकों के करियर में 50 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। सुनील दत्त को इस दुनिया से गये हुए 10 वर्ष हो गये हैं लेकिन उनकी यादें और फिल्में आज भी लोगों के जहन में ताजा हैं। उनकी फिल्मों में आज भी ताजगी है। सुजाता, मदर इंडिया, रेशमा और शेरा, मिलन, नागिन, जानी दुश्मन, पड़ोसन, जैसी फिल्मों से वो हमेशा याद आते रहेंगे। सुनील दत्त जब फिल्मों में आए तो वो दौर राजकपूर दिलीप कुमार देव आनन्द जैसे चोटी के स्टारों के इर्द गिर्द था, लेकिन सुनील दत्त ने धीरे-धीरे अपनी कौशलता से और अपने अभिनय से सबको चौंका दिया और बहुत जल्द ही सबके दिलों पर राज करने लगे और तो और अपने मधुर व्यवहार की वजह से सबके दिलों पर छा गए। और अपने समकालीन अभिनेताओं के दिलों पर भी चढ़ गए। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारतीय राजनीति में भी सार्थक भूमिका निभाई।

मनमोहन सिंह की सरकार में 2004 से 2005 तक वे खेल एवं युवा मामलों के कैबिनेट मंत्री रहे। उनके पुत्र संजय दत्त भी फिल्म अभिनेता हैं। उन्होंने 1984 में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर मुम्बई उत्तर पश्चिम लोक सभा सीट से चुनाव जीता और सांसद बने। वे यहां से लगातार पांच बार चुने जाते रहे। उनकी मृत्यु के बाद उनकी बेटी प्रिया दत्त ने अपने पिता से विरासत में मिली वह सीट जीत ली। भारत सरकार ने 1968 में उन्हें पद्मश्री सम्मान प्रदान किया। इसके अतिरिक्त वे बम्बई के शेरिफ भी चुने गए।

मुश्किल दौर से गुजरे

नरगिस को जब कैंसर हुआ तो वो बहुत मुश्किल दौर से गुजरे नरगिस के इलाज के लिए वो अमेरिका में चक्कर लगाते रहते थे, नरगिस के इलाज के लिए बहुत परेशान रहते थे, लेकिन आखिर बहुत कोशिशों के बावजूद वो नरगिस को बचा नहीं पाए। और नरगिस उन्हें छोडकर इस दुनिया से चली गईं। उसके बाद संजय दत्त भी बुरी लतों में पड़ गये और वो ड्रग्स के आदि हो गए। जिसके चक्कर में उनका संपर्क अंडरवर्ल्ड के लोगों से हो गया और उनका नाम अंडरवर्ल्ड के लोगों से भी जुड़ गया और फिर बॉम्बे बम ब्लास्ट में भी उनका नाम आ गया। उनके पास उसी दौरान एक रॉयफल बरामद होने से उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 18 महीने जेल में बिताने पड़े जिसके लिए सुनील दत्त ने उन्हें बाहर लाने के लिए दिन-रात एक कर दिया इसी तरह उनके ड्रग्स की लत के लिए भी सुनील दत्त ने बहुत जतन किए।

आखिर संघर्ष करते-करते एक दिन 25 मई 2005 को वो इस दुनिया से विदा हो गए। और हमारे बीच अपनी अनमोल यादों को छोड़ गए जो हमें आज भी बहुत प्यार और मोहब्बत का एहसास कराती हैं।

नरगिस और सुनील दत्त के प्यार की कहानी किसी बॉलीवुड स्टोरी से कम नहीं है। फिल्म की शूटिंग के दौरान सेट पर आग लग जाने के बाद सुनील दत्त ने नरगिस की जान बचाई और इस वक्त दोनों ने एक दूसरे को अपना दिल दे दिया। नरगिस और सुनील दत्त के तीन बच्चे हुए एक पुत्र संजय दत्त, जो कि खुद बॉलीवुड में सुपर स्टार बन चुके थे, दो लड़कियां प्रिया दत्त जिन्होंने पापा की सीट से चुनाव लड़ा और सांसद बनीं, दूसरी लडकी नम्रता दत्त जो कि फैशन डिजायनर हैं और राजेन्द्र कुमार के बेटे कुमार गौरव की पत्नी हैं। नरगिस ने फिल्मों के अलावा सामाजिक कार्य में भी अपनी एक अलग पहचान बनाई। उन्होंने मानसिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए भी काम किया। नरगिस का कैंसर की बीमारी के कारण निधन हो गया।

भारत में लांचिंग के लिए तैयार नई स्कोडा ऑक्टाविया आरएस

स्कोडा इंडिया ने आधिकारिक रूप से पुष्टि कर दी है कि नई स्कोडा ऑक्टाविया आरएस भारत में 17 अक्टूबर 2025 को लॉन्च की जाएगी। कंपनी ने बताया कि इस पर प्री-बुकिंग 6 अक्टूबर 2025 से शुरू होगी, जो केवल स्कोडा इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट पर ही की जा सकेगी।

लॉन्च और बुकिंग्स

कंपनी के मुताबिक यह परफॉर्मेंस सेडान भारत में सीमित यूनिट्स में उपलब्ध होगी और इसे पूरी तरह से तैयार यूनिट के रूप में लाया जाएगा। इसकी अनुमानित कीमत 45 से 50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच होगी। ऑक्टाविया आरएस की कहानी भारत में 2004 से शुरू होती है, जब इसे पहली बार लॉन्च किया गया था। इसके बाद 2011 में लौरा वीआरएस, फिर 2017 में ऑक्टाविया वीआरएस 230 और बाद में वीआरएस 245 को पेश किया गया।

9,26,000 से ज्यादा गाड़ियों की डिलिवरी

वैश्विक स्तर पर, स्कोडा ने 2024 में 9,26,000 से ज्यादा वाहनों की डिलीवरी की और अपनी नेक्स्ट लेवल स्कोडा रणनीति के तहत भारत, वियतनाम और आसियान जैसे प्रमुख बाजारों में और विस्तार करने का लक्ष्य रखा है। भारत में कंपनी वर्तमान में 310 से ज्यादा ग्राहक सेवा केंद्र के साथ 177 से ज्यादा शहरों में काइलैक एसयूवी, कुशाक एसयूवी, कोडियाक एसयूवी और स्लाविया सेडान की खुदरा बिक्री करती है।

स्कोडा ऑटो इंडिया के ब्रांड डायरेक्टर आशीष गुप्ता ने कहा कि इस साल की शुरुआत में हमने वादा किया था कि एक वैश्विक आइकन भारत लौटेगा। आज हमें गर्व है कि हम उस वादे को पूरा कर रहे हैं। ऑक्टाविया आरएस सिर्फ एक कार नहीं, बल्कि एक भावना है, जिसने दो दशकों से दुनियाभर के ऑटोमोटिव उत्साहियों के बीच जुनून जगाया है। भारत में इसका लॉन्च परफॉर्मेंस और ड्राइविंग स्पिरिट की एक नई परिभाषा तय करेगा।

ऑक्टाविया वीआरएस 230 में 2.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया था, जो 230 पीएस पावर, 350 एनएम टॉर्क, 250 किलो मीटर प्रति घंटा टॉप स्पीड और 0-100 किलो मीटर प्रति घंटा की स्पीड सिर्फ 6.8 सेकंड में पकड़ने की क्षमता रखता था। इसकी कीमत 24.62 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) थी। इसके बाद वीआरएस 245 आई, जिसे भारतीय ग्राहकों से शानदार रिस्पॉन्स मिला। अब कंपनी एक बार फिर नई ऑक्टाविया आरएस के साथ वापसी कर रही है। संभावना है कि इसमें 2.0रु टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो 264 बीएचपी पावर और 370 एनएम टॉर्क जनरेट करेगा। यह कार 250 किलो मीटर प्रति घंटा टॉप स्पीड और 0-100 किलो मीटर प्रति घंटा केवल 6.4 सेकंड में पकड़ने का दावा करती है।

Xiaomi ने लॉन्च की Robot Vacuum 5 सीरीज जो खुद को भी रखती है साफ

Xiaomi कंपनी ने यूरोप में अपनी लेटेस्ट Robot Vacuum 5 सीरीज को लॉन्च कर दिया है, जिसमें Robot Vacuum 5 और 5 Pro मॉडल शामिल हैं। ये वैक्यूम क्लीनर सिर्फ सफाई ही नहीं करते, बल्कि खुद को गर्म पानी से धोने और सुखाने की स्मार्ट टेक्नोलॉजी से भी लैस हैं। 140 मिनट के दमदार रनटाइम और कई एडवांस फीचर्स के साथ, ये डिवाइस घर की सफाई के अनुभव को पूरी तरह से बदलने का वादा करते हैं। आइए, जानते हैं इन नए रोबोट वैक्यूम क्लीनर्स की कीमत और स्पेसिफिकेशन्स के बारे में सब कुछ।

स्मार्ट फीचर्स और ऑटोमैटिक क्लीनिंग स्टेशन Xiaomi Robot Vacuum 5 सीरीज का सबसे बड़ा हाईलाइट इसका सेल्फ-ऐप्टीइंग स्टेशन है। यह स्टेशन सिर्फ डिवाइस को चार्ज ही नहीं करता, बल्कि कई स्मार्ट काम भी करता है। इसमें 80°C पर गर्म पानी से मॉप (पोछा) धोने की सुविधा है, जिससे जिद्दी दाग-धब्बे भी आसानी से साफ हो जाते हैं। मॉप धुलने के बाद, स्टेशन उसे गर्म हवा से सुखा भी देता है, ताकि उसमें नमी और बदबू न रहे। इसका 2.5 लीटर का डस्ट बैग 75 दिनों तक का कचरा स्टोर कर सकता है, यानी आपको बार-बार इसे खाली करने की झंझट से छुटकारा मिल जाएगा।

पावरफुल परफॉरमेंस और लंबी बैटरी लाइफपरफॉरमेंस के मामले में यह सीरीज बेहद शक्तिशाली है। दोनों मॉडल्स में 20,000 Pa की जबरदस्त सक्शन पावर दी गई है, जो धूल, पालतू जानवरों के बाल और बड़े कचरे को भी आसानी से खींच लेती है। इसमें dToF (डायरेक्ट टाइम ऑफ लाइट) स्मार्ट रडार टेक्नोलॉजी है, जिसकी मदद से यह 9.5 सेमी ऊंचे फर्नीचर के नीचे भी आसानी से जाकर सफाई कर सकता है। बैटरी की बात करें तो इसमें 5,200 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो एक बार फुल चार्ज होने पर 140 मिनट तक लगातार सफाई कर सकती है। इसे फुल चार्ज होने में करीब 6 घंटे लगते हैं।

दूसरे हाथों में पहुंचते ही डिलीट हो जाएंगे रिकार्ड

अधिकांश लोगों को मोबाइल फोन खो जाने का उतना अफसोस नहीं होता जितना कि उसमें मौजूद डेटा के खो जाने या फिर गलत हाथों में पहुँच जाने को होता है। बड़ी कंपनियों के अधिकारियों और सरकारी नौकरशाहों के लिए तो यह बेहद चिंता का मुद्दा बन जाता है। इन्हीं चिंताओं के मद्देनजर एक अदद ऐसे स्मार्टफोन की तलाश लंबे समय से की जाती रही है जो या तो गुम ही न हो पाए और अगर हो जाए तो कम से कम उसमें मौजूद डेटा गलत हाथों में न पड़ने पाए। बहरहाल, हैकर तो हैकर हैं। उनके हाथ में अगर कोई फोन पहुंच जाए तो भले ही उसमें सिक्यूरिटी के कितने भी ठोस इंतजाम क्यों न हों।

आपके डेटा की सुरक्षा की गारंटी नहीं ली जा सकती। ऐसे में एक नये स्मार्टफोन ने इस समस्या के समाधान की उम्मीद जगाई है। इस फोन का नाम है, ब्लैक फोन और इसे बनाया है मशहूर विमान निर्माता कंपनी बोइंग ने। बोइंग ने हाल ही में इस फोन का प्रदर्शन किया, जो है तो किसी भी आम स्मार्टफोन जैसा ही, लेकिन फर्क यह है कि वह एक अदृश्य सुरक्षा आवरण से लैस है। ब्लैक फोन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अगर वह गलत हाथों में पड़ जाता है तो वह अपने भीतर मौजूद सारी सूचनाओं को खुद ही नष्ट कर देता है। जब कोई शख्स कई बार कोशिश करने के बाद भी सही पासवर्ड डालने में नाकाम रहता है और उसके बाद वह स्मार्टफोन के केस को खोलने की कोशिश करता है, तो फोन में मौजूद सुरक्षा प्रणाली समझ जाती है कि कोई व्यक्ति उसके अनधिकृत इस्तेमाल की कोशिश कर रहा है। नतीजा, तीस सेकंड के भीतर ही समूचे डेटा को डिलीट करने के साथ-साथ यह फोन अपनी संचार तथा संचालन प्रणाली को भी निष्क्रिय कर देता है, जिससे वह इस्तेमाल के काबिल नहीं रह जाता। इसके जरिए किए जाने वाले सभी कॉल एनक्रिप्टेड होते हैं यानी कोई खुफिया एजेंसी या हैकर संचार नेटवर्क में सेंध लगाकर उन्हें सुन नहीं सकता। यह गूगल के एंड्रोइड ऑपरेटिंग सिस्टम से लैस है और सीडीएमए, जीएसएम तथा एलटीई नेटवर्कों में काम कर सकता है। वाइफाई और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मौजूद है। इसका आकार आइफोन से थोड़ा बड़ा है और इसमें ड्युअल सिम कार्ड मौजूद हैं। इसकी बैटरी सोलर पावर से भी चार्ज हो सकती है।

रोजगार

ऑडियो इंजीनियरिंग में बनाए करिअर

नई-नई टेक्नोलाजी ने जीवन के हर क्षेत्र में बदलाव ला दिया है। आज कोई भी व्यवसाय इससे अछूता नहीं है। इसमें ऑडियो इंजीनियरिंग भी शामिल है। व्यवसायिक संगीत के क्षेत्र में ऑडियो इंजीनियरिंग ने अपना एक अलग मुकाम कायम किया है। संगीत से जुड़े क्षेत्रों में ऑडियो इंजीनियरों के लिए कारोबारी अपनी पलकें बिछाए रहते हैं।

ध्वनि और उच्च तकनीकी के संगम का नाम है ऑडियो इंजीरियरिंग। आज टीवी, रेडियो, फिल्मों में ध्वनि के कारनामों से अपने ग्राहकों को आकर्षित करने की होड़ लगी है। आवाज और सुर से जुड़ी दुनिया में नई से नई तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है। ऑडियो इंजीनियर सुरों में तालमेल इलेक्ट्रानिक तरीके से करते हैं। ऑडियो इंजीनियर के कमाल की वजह से ही नए-नए डिजिटल रिकॉर्डिंग से फिल्म और टीवी की दुनिया में हलचल पैदा हो रही है। हालांकि ऑडियो इंजीनियरिंग का क्षेत्र भारत में नया है। दूसरे देशों

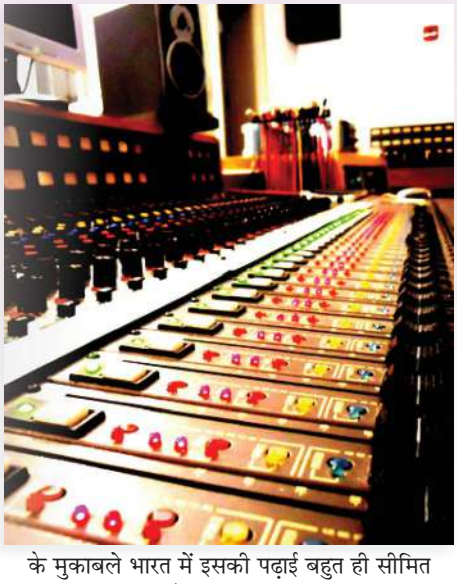

के मुकाबले भारत में इसकी पढ़ाई बहुत ही सीमित संस्थानों में होती है। ध्वनि तकनीकी, माइक्रोफोन और रिकॉर्डिंग तकनीकी, संगीत के सिद्धान्त, डिजिटल ऑडियो स्टूडियो रिकॉर्डिंग तकनीकी, संगीत के सिद्धान्त, डिजिटल ऑडियो रिकॉर्डिंग, कंपनियों की कार्य प्रणाली, लाइव प्रसारण और संगीत में कानून की शिक्षा ऑडियो इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम कोर्स के तहत दी जाती है। इस पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले अभ्यर्थी को सहायक ऑडियो इंजीनियर, स्टूडियो मैनेजर, साउंड इफेक्ट एडीटर साउंड मिक्सर के रूप में मनोरंजन और समाचार टीवी चैनलों, रेडियो और फिल्मों में नौकरी मिल जाती है। भारत में आमतौर पर इस व्यवसाय से जुड़े लोग अपने कॅरियर की शुरुआत स्टूडियो डायरेक्टर के सहायक के तौर पर करते हैं। जैसे-जैसे वे काम सीखते जाते हैं उनका प्रमोशन होता जाता है। क्योंकि भारत में इस पाठ्यक्रम की पढ़ाई सीमित जगहों पर ही होती है। भारत में भी अब कई संस्थाएं इस पाठ्यक्रम की शुरुआत कर चुकी है। मीडिया एजुकेशन कालेज और एसआई टेक्नोलॉजी कालेज से इस पाठ्यक्रम की ज्यादा जानकारी ले सकते हैं।

अदालत में स्ट्रीट डाग

रविन्द्र गिन्नौरे

बिजली के खंबे के पास एक कुत्ता अपनी टांग उठाने वाला ही था कि उसके सामने काला कोट पहने एक आदमी आ खड़ा हुआ, उसने कुत्ते से कहा,

पहचाना मुझे..! कुत्ते ने बड़ी हैरत भरी नज़रों से उस आदमी को देखा कि मुझे इतनी इज्जत देने वाला इतना साफ, सुथरा आदमी.. आखिर है कौन..! बड़ी उत्सुकता से कुत्ता बोला,

मैं तो आप को नहीं जानता, आप ही बताइए कौन हैं आप।

बड़ी गर्मजोशी से अपना हाथ आगे करता हुआ काला कोट वाला आदमी बोला,

मैं हूं आप का वकील..।

मुझ कुत्ते का वकील...! पर मैंने तो आप को अपना वकील बनाया ही नहीं...। कुत्ते ने कहा।

आप बिल्कुल ठीक कहते हो।आप ने हमें वकील भले नियुक्त नहीं किया है पर हम खुद अदालत में कुत्ता बिरादरी के वकील बन कर खड़े हुए हैं।

कुत्ता हैरान हो गया। वह बोला,

अदालत में हम कुत्तों की वकालत करने वाला इतना बड़ा वकील..! वकील साहब हम कुत्तों को अदालत और वकीलों से क्या भला लेना देना। वैसे सुना है कि अदालत ने स्वत- संज्ञान लेकर कुत्ता बिरादरी पर सुनवाई की तो है, पर हम अपने बचाव के लिए देश का सबसे बड़ा वकील कैसे खड़ा कर सकते हैं..।

वकील बोला, सचमुच आप खड़ा नहीं कर सकते इसलिए ही हम खुद कुत्तों के वकील बन गये।

कुत्ता बोला, सुना है आप एक घंटे की फीस एक लाख रुपए लेते हो..।

बिलकुल ठीक सुना है आप ने। हम देश के बड़े वाले वकील हैं। हमारी फीस बहुत है। हर फसादी, भ्रष्टाचारी, देशद्रोही हमें ही अपना वकील बनाते हैं। कुत्ता बिरदारी बच्चों को, लोगों को सरे-आम काटते हैं, नोंचते हैं। कुत्ते ऐसे ही दहशत फैलाते हैं इसलिए उन्हें शेल्टरों में रखा जाए। अदालत का यह आदेश कुत्तों के साथ अन्याय है इसलिए ही मेरे जैसा एक और वकील कुत्तों की वकालत करने खड़ा हुआ है। वकील ने कुत्ते को बताया।

आखिर स्ट्रीट डाग के हिमायती आप क्यों बन बैठे हैं। हमारे से आप को कुछ भी नहीं मिलने वाला है। कुत्ते ने कहा।

वकील ने कुत्ते को समझाते हुए कहा,

हम आप से कुछ भी नहीं चाहते। बस आप अपना काम करते रहो। पर्यावरण संतुलन के लिए कुत्तों का बना रहना जरूरी है।

कुत्ते ने कहा, पर अदालत तो हमें शेल्टर हाऊस में बंद करने वाली है।

बस इसी बात पर हम अदालत में आप के हक के लिए लड़ रहे हैं। शेल्टर हाऊस में कुत्ते बंद रहेंगे तो उनकी स्वतंत्रता छिन जाएगी। कुत्ते तो सर्वत्र व्याप्त होना चाहिए ...। वकील ने कहा।

कुत्ते ने कहा,

वो तो सब ठीक है. पर आप की फीस तो हम कभी भी नहीं पाएगें..।

आप फीस वीस की चिन्ता नहीं करें। आपकी कुत्ता बिरादरी के कारण देश विदेश की बहुत सारी कंपनी चलती है।

कुत्ते काटे तो इंजेक्शन लगता है। रेबीज की बीमारी फैले तो वैक्सीन चलती है। कुत्तों से जेमी लोग अस्पताल पहुंचते हैं। बहुत की रोजी- रोटी चलती है कुत्तों के कारण और हमारी भी..! वकील ने कहा।

हम कुत्ते तो अपनी आदत से मजबूर हैं। खंबा देखें तो हमारी टांग अपने आप उठ जाती हैं। बच्चों को देखें तो उनको काटने, नोंचने का मन करता है। कुत्ते ने कहा

बस.. बस हम यही चाहते हैं कि कुत्ते तो कुत्ते बनें रहें। वकील ने कहा।

आप आदमी तो हैं या फिर या फिर कोई और..! क्या काला कोट पहनकर आप कुछ और तो नहीं बन गये। आप कहीं हम कुत्तों को किसी मुसीबत में तो नहीं फंसा रहे हो। कुत्ते ने वकील से सवाल किया।

कुत्ता बिरादरी को मेरी बात समझ नहीं आएगी। हम आद?मी जरूर हैं, बड़ी कंपनियों के वकील हैं। जो वे चाहते हैं हम वही करते हैं। हमें आम आदमियों से कोई लेना देना नहीं है। वकील ने कहा।

कुत्ता बोला,

वह सब तो मैं समझ गया कि आप इंसान तो दिखते हो पर इंसानों से अलग हो। कुत्ते जैसे तुच्छ जानवरों के लिए आप जी जान लगा रहे हो। भला क्यों, हम भी तो जाने..।

यह डीप राजनीति है। कुत्ते रहेंगे तो रेबीज़ वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां चलेगी। वकील ने कहा

कुत्ता सोचने लगा, हम हिंसक बनते जा रहें हैं। सीधा खंबा पर हमारी टांग का सदियों पुराना रिश्ता है। पर ताज्जुब है कि हिंसक खूंखार होते स्ट्रीट डाग पर इन्सान का ख़ास वर्ग हमारे लिए पलक पांवड़े बिछाए हुए हैं। इक्कीसवीं सदी में खास आदमी और कुत्तों के बीच एक अनैतिक समझौता के लिए क्यों लालायित हो रहें हैं। आखरि में कुत्ता हैरान हो गया। वह बोला,

आप तो शरीर से आदमी दिखते हो परन्तु आपका काम हम से ज्यादा ख़तरनाक है ?

मेरी इतनी तारीफ करने के लिए शुक्रिया... कहते हुए कुत्तों का वकील चला गया।

गणपतिजी विदा हो गए तो रिद्धि-सिद्ध शुभ-लाभ कैसे रहेंगे?

विनय पांडेय

दस दिनों तक भगवान गणेश के संग उत्सव की अनुभूति के बाद अनंत चतुर्दशी को हवन पूजन के साथ उत्सव की श्रृंखला का समापन होगा, विसर्जन का समय आ जायेगा। पिछले दिनों एक प्रश्न आया कि गणपति का विसर्जन क्यों? विदाई क्यों? जीवन से गणपति विदा हो गए, तो फिर जीवन मे रिद्धि-सिद्धि कैसे रहेंगी, शुभ-लाभ कैसे रहेंगे, संतोषी प्रवृति कैसे रहेगी। सभी गणपति के परिवार से ही तो हैं? कोई भी पूजन या पराक्रम कैसे होगा। वाकई गणेश जी की जरूरत तो हमें हर वक्त है, फिर विदाई कैसे? विचार किया तो उत्तर मिला विसर्जन मूर्ति का किया जाता है, भक्ति का नही।

मान्यता के अनुसार इन दस दिनों में गणपति मूर्त रूप में हमारे साथ होते हैं, वैसे ही जैसे नवरात्रि में देवी और पितृ पक्ष में पितर। इसलिए ये दस दिनों के मूर्त रूप में साथ के उत्सव का समापन है, अलविदा नहीं है। अमूर्त रूप में तो गणपति हों या देवी सदा साथ ही रहते हैं। ईश्वर तो प्रकृति की तरह दसों दिशाओं और तीनों कालों में व्याप्त है, उसे कौन विसर्जित कर सकता है। प्रकृति के पांच तत्वों से वह हमारे उत्साहवर्धन और आनंद के लिए प्रतीकात्मक मूर्त रूप में आता है और पुनः असीम प्रकृति के अमूर्त रूप में रूपांतरित हो जाता है। श्री गणेश तो स्वयं अनादि हैं और अनंत भी।

मूर्ति विसर्जन अपने गहरे आध्यात्मिक अर्थ में जीवन की अनित्यता, परिवर्तन को अपनाने और अहंकार व नकारात्मकता को ईश्वर में विसर्जित करने का संदेश देता है। यह संकेत है कि भौतिक जगत में हर आरंभ का एक समापन होता है। मिट्टी की मूर्ति का मिट्टी में विलीन होना भी प्रतीक है कि जो लिया है, उसे लौटाना पड़ता है। इसलिए विसर्जित की जाने वाली मूर्ति का निर्माण पंचतत्वों से किया जाता है ताकि पंचतत्वों का पुनः संविलयन हो सके और प्लास्टर आफ पेरिस का प्रयोग रीति-नीति के विपरीत माना जाता है।

विसर्जन की पौराणिक कथा भी है। कथा के अनुसार, गणेश जी लगातार 10 दिनों तक लगातार महाभारत ग्रंथ लिखते रहे, जिस कारण उनके शरीर का तापमान बढने लगा। व्यास जी ने उन्हे मिट्टी का लेप लगाया, हर दिन नैवेद्य अर्पित किए और लेखन पूर्ण होने पर उनसे सरोवर में स्नान करने की विनती की। गणेश जी को शीतलता मिली और मिट्टी का लेप घुल गया। तभी से यह परंपरा चली कि गणपति की मूर्ति को 10 दिन नैवेद्य भोग अर्पित करें और फिर जल में विसर्जित करें।

यहां हमारे लिए भी संदेश है।

जब हमें भी कोई ऐसा मिले कि जो विघ्नों का सामना करने में मदद करे, बड़े काम में सहारा दे, तो उसके प्रति अपने कर्तव्य को न भूलें। वह हमारे लिए गणपति का अंश ही है। प्रेमपूर्ण मिठास अर्पित करते रहें और हर अभियान के बाद स्नेह से सिंचित करना न भूलें। आधुनिक इतिहास में विसर्जन का बड़ा उत्सव, मेरी सीमित जानकारी में, पेशवाओं के समय शुरू हुआ। पेशवाओं ने सबको संगठित करने के लिए गणेश पूजा पर मूर्ति आंगन से निकाल कर बाहर मंडप में स्थापित की। सभी को दर्शन और छू कर आशीर्वाद लेने का अवसर मिला, इससे आमजन स्वराज की लड़ाई में करीब आये, पर अनंत चतुर्दशी के बाद जब पुनः मंदिर में स्थापना की बात आई तो विवाद हो गया। एक वर्ग कहने लगा कि मूर्ति सार्वजनिक होने के बाद पेशवाई मंदिर में पुनः स्थापित नहीं की जा सकती। विवाद न बढ़े और एकता बनी रहे, इस हेतु बीच का रास्ता निकाल कर धूमधाम से विसर्जन का निर्णय लिया गया।

बाद में लोकमान्य तिलक जी ने इतिहास रचा। सार्वजनिक गणेश पूजा को उत्सव के तौर पर मनाने के लिए जन मानस को प्रेरित किया, दस दिन उत्सव में पंडाल में सब इकठ्ठे हों और अंत मे विसर्जन के जुलूस में एकता प्रदर्शित करें। अंग्रेजों के जमाने मे लोगों को इकठ्ठे खड़े होने के लिए प्रेरित करना स्वतंत्रता आंदोलन की पहली आवश्यकता थी। शिक्षक दिवस पर गणपति जी की चर्चा के बाद एक प्रश्न आया कि यदि ऐसा है तो कई स्कूलों में सरस्वती वंदना होती है (मेरे स्कूल में भी होती थी), गणेश वंदना क्यों नहीं। स्पष्ट कर दूं, गणपति के अप्रतिम संदेशों /शिक्षाओं के जिक्र का अर्थ यह कतई नहीं कि कहीं कोई तुलना है। देव स्वरूपों की तुलना अकल्पनीय भी है और अवांछनीय भी। फिर भी प्रश्न के संदर्भ में मुझे लगता है विद्यालय ज्ञान एवं कौशल के केंद्र माने जाते हैं और ज्ञान एवं कौशल की अधिष्ठाता देवी सरस्वती हैं, इसलिए स्वाभाविक है कि कई स्कूलों में उनकी वंदना होती है। जैसा दूसरे दिन के आलेख में जिक्र था, ज्ञान और बुद्धि समानांतर हैं, पर अलग हैं। ज्ञान/कौशल बताता है कैसे करें, बुद्धि बताती है क्या करें।

एक प्रश्न यह भी आया कि गणेश जी और सरस्वती जी का क्या रिश्ता है, यह भी कि गणेश जी और लक्ष्मी जी का क्या रिश्ता है। दिलचस्प ये कि दोनों प्रश्न पूछने वालों ने कारण एक ही बताया -कुछ चित्रों में गणेश जी में लक्ष्मी जी के साथ दिखते हैं और कुछ में सरस्वती जी के साथ और कुछ में तीनों साथ साथ। गणेश जी और लक्ष्मी जी का संबंध तो कथाओं में स्पष्ट है। कथा के अनुसार गणेश जी लक्ष्मी जी के दत्तक पुत्र है। यह भी कि जब इस बाबत लक्ष्मी जी ने पार्वती जी से विनती की तो जगदेबा इस शर्त पर तैयार हुईं कि लक्ष्मी जी सदा गणेश जी को अपने साथ रखेंगी और जहां गणेश का आदर नहीं होगा, वहां वो भी नहीं रुकेंगी। जहां तक सरस्वती जी और गणेश जी का संबंध है, कुछ कथाओं में इन्हें भाई बहन बताया गया है और कुछ में बुआ-भतीजा। मेरी सामर्थ्य नहीं कि इस पर कुछ निर्णयात्मक कहूँ।

परन्तु प्रतीकों को देखें। लक्ष्मी जी धन एवं समृद्धि की प्रतीक हैं, सरस्वती जी ज्ञान और कौशल की और भगवान गणेश बुद्धि के। धन अर्जन के लिए ज्ञान /कौशल की आवश्यकता होती है और धन को संभालने के लिए बुद्धि की। बुद्धि और समझ के बिना न धन का सही उपयोग हो सकता है और न ही ज्ञान का सही मार्गदर्शन। इस नाते जीवन मे आनंद मंगल केबलिये तीनों की आवश्यकता एक साथ ही होती है।

प्रतीकात्मक एक श्रृंखला और है-

लक्ष्मी जी का एक अर्थ है आनंद और यह कमल के प्रतीक से प्रकट होता है, जो हमारे मन/मस्तिष्क का केंद्र है। सरस्वती मन/मस्तिष्क के दाहिने भाग का प्रतिनिधित्व करती हैं, इसी भाग से सभी अमूर्त कलाएँ संपन्न होती हैं। इसे ज्ञान या जानना कहते हैं। गणेश मन/मस्तिष्क के बाएँ भाग का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसी भाग से सभी व्यावहारिक कलाएँ संपन्न होती हैं। इसे विज्ञान या करना कहते हैं। जब उचित ज्ञान और उचित कर्म एक साथ मिलते हैं, तो योग होता है जो मस्तिष्क के केंद्र में स्थित आनंद को जागृत करता है। इस दृष्टि से भी तीनों का वंदन साथ साथ किया जाता है।

इस उत्सव के अंतिम दिन बस यही विनम्र प्रार्थना कि प्रतीकों के देवता गणपति जी का पूजन स्वयं प्रतीक बन कर न रह जाए। गणपति हमें सद्बुद्धि दें कि हम इतने प्रतीकों में से किसी से कुछ तो सीख सकें।

गणपति की कृपा से जब मोरया गोसावी जी का नाम उनसे जुड़ कर गणपति बप्पा मोरया के रुप में अमर हो सकता है तो गणपति की कृपा से हमारे प्रयास भी कुछ तो सफल हो ही सकते हैं।

एक बार सच्चे दिल से बोलें तो सही
गणपति बप्पा मोरया...
इति श्री गणपति प्रसंग समाप्तम...

व्रत त्योहार सितंबर 2025

01 अक्टूबर	बुधवार महानवमी, सरस्वती बलिदान
02 अक्टूबर	गुरुवार सरस्वती विसर्जन, विजयदशमी, गांधीजयंती
03 अक्टूबर	शुक्रवार भारत मिलाप, पापांकुशा एकादशी
04 अक्टूबर	शनिवार प्रदोष व्रत, विश्व पशु दिवस
06 अक्टूबर	सोमवार पूर्णिमा व्रत, शरद पूर्णिमा, काजोगरा पूजा
07 अक्टूबर	मंगलवार कार्तिक स्नान, वाल्मीकि जयंती, पूर्णिमा
10 अक्टूबर	शुक्रवार करवा चौथ, संकष्टी गणेश चतुर्थी
11 अक्टूबर	शनिवार रोहिणी व्रत
13 अक्टूबर	सोमवार कालाष्टमी, अहोई अष्टमी
17 अक्टूबर	शुक्रवार रामाएकादशी, तुलासंक्रांति, गोवत्स द्वादशी
18 अक्टूबर	शनिवार प्रदोष व्रत, धनतेरस
19 अक्टूबर	रविवार काली चौदस, मास शिवरात्रि
20 अक्टूबर	सोमवार नरक चतुर्दशी
21 अक्टूबर	मंगलवार भौमवती अमावस्या, अमावस्या, दिवाली
22 अक्टूबर	बुधवार अन्नकूट, चंद्र दर्शन, गोवर्धन पूजा
23 अक्टूबर	गुरुवार भाई दूज
25 अक्टूबर	शनिवार वरद चतुर्थी
26 अक्टूबर	रविवार लाभ पंचमी
27 अक्टूबर	सोमवार सोमवार व्रत, षष्ठी, छठ पूजा
29 अक्टूबर	बुधवार बुधाष्टमी व्रत
30 अक्टूबर	गुरुवार गोपाष्टमी, दुर्गाष्टमी व्रत
31 अक्टूबर	शुक्रवार अक्षय नवमी

दिवस

1 अक्टूबर	अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस
	अंतरराष्ट्रीय कॉफी दिवस
	विश्व शाकाहारी दिवस
	अंतरराष्ट्रीय संगीत दिवस
2 अक्टूबर	अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस
	पर्यावास दिवस
4 अक्टूबर	विश्व पशु कल्याण दिवस
	विश्व अंतरिक्ष सप्ताह
	विश्व शिक्षक दिवस
	विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस
	विश्व मुस्कान दिवस
	विश्व कपास दिवस
	भारतीय वायु सेना दिवस
9 अक्टूबर	विश्व डाक दिवस
	भारतीय विदेश सेवा दिवस
10 अक्टूबर	विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस
	राष्ट्रीय डाक दिवस
11 अक्टूबर	अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस
12 अक्टूबर	विश्व गठिया दिवस
	विश्व दृष्टि दिवस
13 अक्टूबर	संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण दिवस, विश्व अंडा दिवस
14 अक्टूबर	विश्व मानक दिवस
15 अक्टूबर	विश्व छात्र दिवस
15 अक्टूबर	अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस
15 अक्टूबर	विश्व सफेद बेंत दिवस
	वैश्विक हाथ धुलाई दिवस
16 अक्टूबर	विश्व खाद्य दिवस
	विश्व एनेस्थीसिया दिवस
17 अक्टूबर	महर्षि वाल्मीकि जयंती
	अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस
20 अक्टूबर	राष्ट्रीय एकजुटता दिवस
	विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस
21 अक्टूबर	राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस
22 अक्टूबर	अंतरराष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस
24 अक्टूबर	संयुक्त राष्ट्र दिवस
24 अक्टूबर	आईटीबीपी स्थापना दिवस
	विश्व पोलियो दिवस
26 अक्टूबर	जेमू और कश्मीर विलय दिवस
27 अक्टूबर	विश्व दृश्य-श्रव्य विरासत दिवस
29 अक्टूबर	विश्व स्ट्रोक दिवस
30 अक्टूबर	विश्व बचत दिवस
31 अक्टूबर	विश्व शहर दिवस
31 अक्टूबर	एकता दिवस
31 अक्टूबर	मृतकों की आत्मा के उठने का दिन

छत्तीसगढ़ में शासकीय अवकाश

सार्वजनिक अवकाश
2 अक्टूबर दशहरा (विजयादशमी) / महात्मा गांधी का जन्मदिवस
20 अक्टूबर दीवाली (दीपावली)
27 अक्टूबर छठ पूजा
ऐच्छिक अवकाश
1 अक्टूबर दशहरा (महानवमी)
4 अक्टूबर डॉ. सैयदना साहब का जन्म दिवस
7 अक्टूबर महर्षि वाल्मिकी टेकचन्द जी महाराज का समाधि उत्सव /कुवांर पूर्णिमा, करम परब (त्यौहार) जयंती / महाराजा अजमोद देव जयंती /
10 अक्टूबर करवाचौथ व्रत
19 अक्टूबर दीपावली (दक्षिण भारतीय)
21 अक्टूबर दीपावली का दूसरा दिन (गोवर्धन पूजा)
23 अक्टूबर भाई दूज (दीपावली)
28 अक्टूबर भगवान सहस्त्रबाहु जयंती

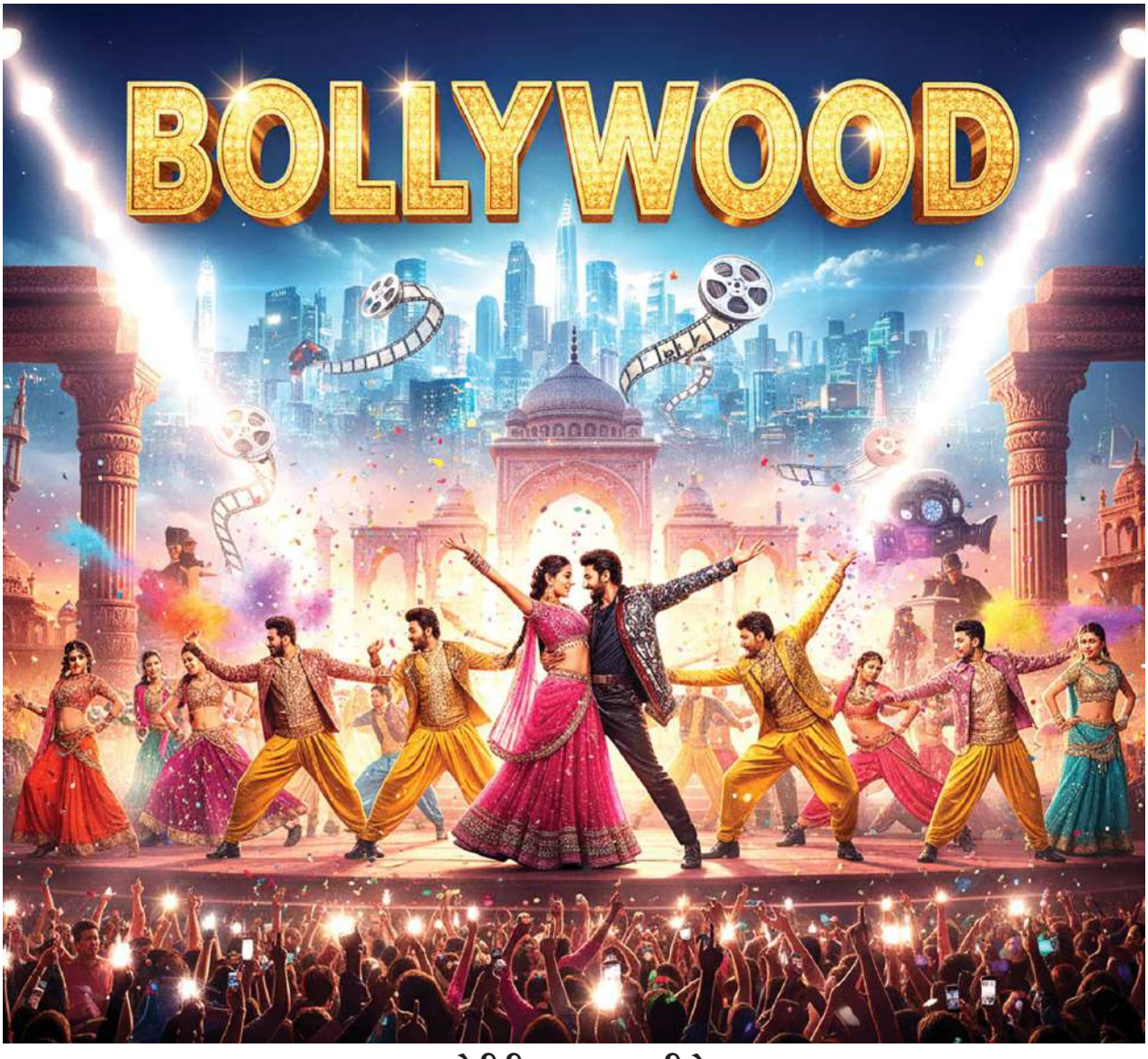

ओटीटी पर इस महीने

1. सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी
   02 अक्टूबर 2025 वरुण धवन, जान्हवी कपूर
2. वैपायर सागा
   11 अक्टूबर 2025 अब्दुल अदनान, जुबेर के खान
3. भोगी
   14 अक्टूबर 2025 शारवानंद , अनुपमा परमेश्वरन
4. गो गोवा गॉन 2
   15 अक्टूबर 2025 सैफ अली खान , कुणाल खेमू
5. गोलमाल फाइव
   19 अक्टूबर 2025 अजय देवगन , श्रेयस तलपड़े
6. एक दीवाने की दीवानियत
   21 अक्टूबर 2025 हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा
7. मलंग 2
   30 अक्टूबर 2025 आदित्य रॉय कपूर, दिशा पटानी
8. इलियाराजा
   अक्टूबर 2025 धनुष
9. नेटवर्कर
   अक्टूबर 2025 ऋषभ पाठक, विक्रम कोचर
10. जानम तेरी कसम अक्टूबर 2025
11. जिन्न
    अक्टूबर 2025 रवि मोहन, कृति शेट्टी
12. हरकारा अक्टूबर 2025 बालाजी मुरुगादोस
13. आशिकी
    3 अक्टूबर 2025 कार्तिक आर्यन, श्रीलीला

Install Solar Rooftop Systems and Shine Brighter with

UNDER PM SURYA GHAR MUFT BIJLI YOJANA

SUBSIDY AVAILABLE

2 KW SYSTEM
BASE COST : Rs. 1,60,000
Subsidy
रू. 60000 + रू. 30000 = रू 90,000

3 KW SYSTEM
BASE COST : Rs. 2,10,000
Subsidy
रू. 78000 + रू. 30000 = रू 108,000

: BHILAI OFFICE :
Mob. : 97707 51513, 70009 32521
72/A, Light Industrial Area, Chhawani, Bhilai (C.G.)
Email: info.hssolarenergy@gmail.com

: RAIPUR OFFICE :
Mob.: 97707 51513, 70009 32521
B.O. : Dubey Colony, Raipur (C.G.)
Email: info.hssolarenergy@gmail.com